

## फ्रांस के नीस में मोदी-मैक्रों ने द्विपक्षीय बैठक की...

# भारत सॉल्यूशन लेने वाला नहीं देने वाला देश : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, 14 जून 2026। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों के साथ रविवार को द्विपक्षीय बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी शामिल रहे। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ-टेक, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इससे पहले दोनों नेताओं ने 'भारत इनोवेट्स 2026' प्रोग्राम का उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के बाद राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी को नीस के पास स्थित विला कैरीलोस घुमाने ले गए। यह फ्रांस की प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है।

### भारत इनोवेट्स युवाओं के लिए बड़ा मंच

मोदी ने कहा कि 'भारत इनोवेट्स' भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय निवेश को जोड़ने वाला मंच है। इससे भारतीय स्टार्टअप, युवा उद्यमियों और नए आईडिया को दुनिया के बड़े निवेशकों और विशेषज्ञों तक पहुंचने का मौका मिलेगा।

### भारत स्टार्टअप का बड़ा केंद्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हैं, लेकिन भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप भारत के साथ-साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास में भी योगदान दे रहे हैं।

और फ्रांस का रिसर्च सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। यह भरोसे, साझा सोच और साझा लक्ष्यों पर आधारित है। दोनों देश मिलकर दुनिया की कई बड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं।



### नई तकनीकें बदलेंगी भविष्य...

मोदी ने कहा कि दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन हर चुनौती नए मौके भी लेकर आती है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक जैसी नई तकनीकें आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगी।

### युवा दे रहे हैं समस्याओं का समाधान...

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में स्टार्टअप क्रांति चल रही है। देश के युवा नई सोच के साथ लोगों की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं।

### भारत ग्लोबल इनोवेशन का नेतृत्व कर रहा...

मैक्रों ने कहा कि भारत रिसर्च, इनोवेशन और तकनीकी विकास के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत हर साल यूरोप और अमेरिका को मिलाकर जितने इंजीनियर तैयार होते हैं, उतने इंजीनियर तैयार करता है।

## टीएमसी के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में शामिल होंगे



### बंगाल बीजेपी प्रभारी और लोकसभा स्पीकर से मिले, काकोली बोलीं- एनडीए को हमारा समर्थन

कोलकाता, 14 जून 2026। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी के कई बागी सांसदों ने रविवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले बागी गुट के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर भी बैठक की। बैठक के बाद बागी सांसदों में शामिल काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी के 20 सांसद नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में विलय करेंगे। काकोली ने कहा- आगे हम देशहित में काम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। बागी सांसदों से पहले ममता के समर्थन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष लोकसभा स्पीकर से मिले। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ 20 सांसदों या 60 विधायकों से नहीं बनी। ममता बनर्जी ने ही इस पार्टी को खड़ा किया है, इसलिए वही असली पार्टी है।

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बिरला को लेटर लिखकर कहा कि सदन में टीएमसी को केवल एक पार्टी के रूप में देखा जाए। किसी दूसरे गुट को मान्यता न दी जाए। बंगाल में टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा 13 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें 4 ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कीर्ति आजाद ने कहा- महाराष्ट्र में जो हुआ वह गलत था, इसलिए बागी नेताओं के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक आवेदन सौंप दिया गया है जिसकी हार्ड कॉपी स्पीकर कार्यालय ने प्राप्त कर ली है।

बागी गुट की सांसद काकोली घोष का दावा है कि उनके पास अब 22 सांसदों का समर्थन है। पहले काकोली ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा किया था। इसके बाद 19 सांसदों के साइन वाला एक लेटर भी सामने आया था। दिल्ली पहुंचते ही सायोनरी ने कहा... मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। सही समय आने पर ही बोलूँगी। ममता ने सायोनरी और माला को पार्टी के पदों से हटा दिया है। सायोनरी पार्टी की युथ विंग की अध्यक्ष थीं। सायोनरी घोष और माला रॉय रविवार को कोलकाता से दिल्ली पहुंचीं। वहीं बागी सांसद जगदीश बसुनिया ने बताया कि हमारा गुट आज लोकसभा स्पीकर से मिलेगा।

## एक ही परिवार के चार लोगों की सदृग्ध परिस्थितियों में मौत

वाशिम, 14 जून 2026। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से बेहद दर्दनाक और रहस्यमय घटना सामने आई है। जिले के मालेगांव तहसील स्थित तिवली गांव में एक ही परिवार के चार सदस्य मृत पाए गए। खेत में बने बिजली के टावर से एक व्यक्ति का शव लटका मिला, जबकि कुछ दूरी पर एक कुएं से उसकी पत्नी और दो मासूम बच्चों के शव बरामद किए गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संतोष तुकाराम बकाल के रूप में हुई है, जो तिवली गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों ने खेत में बने बिजली के टावर से एक व्यक्ति का शव लटका हुआ देखा। इसी दौरान टावर से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं में एक महिला और दो बच्चों के शव तैरते मिले। घटना की सूचना तुरंत शिरपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। ग्रामीणों की मदद से महिला और दोनों बच्चों के शवों को चारपाई के सहारे कुएं से बाहर निकाला गया। बाद में उनकी पहचान संतोष बकाल की पत्नी और उसके दो बच्चों के रूप में हुई। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की खबर फैलते ही गांव में मातम पसर गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मालेगांव के सरकारी अस्पताल भेज दिया। शिरपुर के सब-इंस्पेक्टर इमरान पटान ने बताया कि शाम करीब चार बजे गांव के पुलिस पटिल ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति ने बिजली के टावर पर फंदा लगाकर जान दे दी है। साथ ही पास के कुएं में उसकी पत्नी और दो बच्चों के शव भी मौजूद हैं।

## मुरैना में रेल हादसा... ट्रेन में आग की अफवाह सुनकर कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए, 4 लोगों की मौत

मुरैना, 14 जून 2026। मुरैना जिले के हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशनों के बीच रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद घबराए यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। इसके बाद कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर आ गए और दूसरी लाइन पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे में तीन महिलाओं और एक मासूम बच्चे समेत कुल 4 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक, उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ग्वालियर से मुरैना की ओर जा रही थी। इसी

लाइन पर धौलपुर की ओर से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस वहां पहुंच गई और कुछ यात्री उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही जोआरपी, आरपीएफ और मुरैना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया तथा मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों से संपर्क करने की प्रक्रिया जारी है। इस हादसे के चलते दिल्ली-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर कुछ समय के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा। कई ट्रेनों को रास्ते में रोका गया, जबकि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गईं। बाद में ट्रैक को क्लियर कर रेल यातायात सामान्य किया गया।

## हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल इंटरनेट बंद, गुडसाईं मीड ने आरोपी के घर में आग लगाई, माहौल तनावपूर्ण

विकासनगर, 14 जून 2026। उत्तराखंड के विकासनगर स्थित बैरागीवाला गांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। यहां आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाज कर दिया। आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने मामले को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कई लोग लाठी-डंडों के साथ एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। बैरागीवाला गांव से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने घटना के खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद कर लिया है। वीडियो में लाठी-डंडों से लैस लोग सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो वहीं चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस का कहना है कि विवाद की शुरुआत खेत में पानी लगाने को लेकर हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मामूली कड़मनी हिंसक झड़प में बदल गई। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज में जो हिंसा दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव की गलियों में अचानक हलचल बढ़ जाती है। कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर दौड़ते नजर आते हैं। इसके बाद हमला शुरू हो जाता है।

## देश में डेमोग्राफी बदलाव के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय समिति बनेगी, अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश...

नई दिल्ली, 14 जून 2026। भारतीय सेना ने गुलामी के दिनों यानी औपनिवेशिक दौर की बची-खुची पुरानी परंपराओं को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सेना ने अपने जवानों और अधिकारियों को ड्रेस यानी वर्दी से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत अब औपचारिक कार्यक्रमों में बंद गले वाली स्वदेशी 'बंदी' जैकेट पहनने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही सेरेमोनियल पाउच बेल्ट को हटा दिया गया है और परेड के दौरान निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के लिए हाथ में तलवार रखना अब अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक कर दिया गया है। इन सभी नए और आधुनिक बदलावों की पूरी जानकारी सेना द्वारा जारी किए गए 174 पन्नों के विशेष मैनुअल 'आर्मी यूनिफॉर्मस-2026' में दी गई है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक, ऐसा नियम आखिरी बार आठ साल पहले जारी किया गया था। एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने कहा कि यह कदम सेना के पहनावे को प्रासंगिक और आधुनिक बनाने का एक हिस्सा है।

नई दिल्ली, 14 जून 2026। देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसंख्या के संतुलन को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) में आ रहे अप्रत्याशित बदलावों का गहन अध्ययन करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति को सीमा से सटे संवेदनशील जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का सख्त निर्देश दिया है। गृह मंत्री ने समिति के सदस्यों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे देश के सीमावर्ती इलाकों, बड़े महानगरों और प्रमुख औद्योगिक शहरों का जमीनी दौरा करें। इस दौर का मुख्य उद्देश्य यह सटीक पता लगाना है कि अल्पसंख्यक (इथनोल माइग्रेशन) और अन्य बाहरी कारणों से इन क्षेत्रों की मूल जनसंख्या संरचना में किस तरह के गंभीर बदलाव आ रहे हैं।

## अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच खामेनेई के अंतिम संस्कार का ऐलान, मध्य पूर्व राजनीति में बड़ा बदलाव संभव

नई दिल्ली, 14 जून 2026। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी भीषण सैन्य युद्ध और दोनों पक्षों की ओर से हो रहे विनाशकारी हवाई हमलों के बीच आज एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। वैश्विक व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के कई महीनों से पूरी तरह बंद रहने के बाद, आज दोनों देशों के बीच आर्योजित होने वाली शांति वार्ता पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस कूटनीतिक पहल से दोनों महाशक्तियों के बीच लंबे समय से चला आ रहा यह खूनी संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त होने की उम्मीद जगी है। इसी ऐतिहासिक

को तेहरान के ऐतिहासिक इमाम खुमैनी प्रार्थना स्थल पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद, 6 जुलाई को राजधानी तेहरान की सड़कों पर एक विशाल राष्ट्रीय शोक जुलूस निकाला जाएगा। विदाई का यह सिलसिला यहीं नहीं थमेगा; 7 जुलाई को ईरान के पवित्र शहर क्रोम में और 9 जुलाई को मशहद शहर में विशेष धार्मिक समारोहों का आयोजन किया जाएगा। सभी रस्मों के पूर्ण होने के बाद, अयातुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को मशहद में स्थित इमाम रजा के विश्व प्रसिद्ध और बेहद पवित्र तीर्थस्थल के भीतर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा।

## पटना कोचिंग बवाल में बड़ा मोड़... फरार आरोपी प्रिंस यादव की नेपाल में गोली मारकर हत्या, पटना के कई इलाकों में पुलिस अलर्ट

पटना, 14 जून 2026। बिहार की राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान विवाद से जुड़ एक बेहद सनसनीखेज और बड़ा मामला सामने आया है। मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हिंसक बवाल मामले में फरार चल रहे आरोपी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रैशन आनंद के सगे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बड़ी वारदात के बाद पटना में दोबारा तनाव और बवाल होने की आशंका को देखते हुए पीरबखोर और कदमकुआं जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, खान सर की कोचिंग पर पिछले दिनों हुए पथराव और हंगामे के बाद से ही पुलिस लगातार उपद्रवियों और साजिशकारियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। कानूनी कार्रवाई और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए मूल रूप से बिहार के सुप्रीम जिले का रहने वाला प्रिंस यादव चुपके से सीमा पार कर नेपाल भाग गया था। वह नेपाल के एक स्थानीय गैरट हाउस में कमरा लेकर अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने उसी गैरट हाउस के कमरे के अंदर घुसकर प्रिंस को बेहद करीब से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पटना के दो बड़े कोचिंग सेंटरों के बीच का यह आपसी विवाद अब एक खूनी खेल में बदल चुका है।

## जम्मू में कार और ट्रक की टक्कर हरियाणा के तीन लोगों की मौत

जम्मू, 14 जून 2026। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रविवार को एक ट्रक से कार की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह हादसा नगरोटा के जगती-कारली इलाके में रात करीब 2.15 बजे हुआ, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान हरियाणा के रहने वाले सिकंदर सेफी, शक्ति और मोहित वर्मा के रूप में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि दो अन्य घायलों दीपक वर्मा और कुलदीप शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस विशेष उच्चस्तरीय समिति का औपचारिक गठन किया था। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी डेमोग्राफी में आ रहे इन बदलावों के पीछे छिपे वास्तविक कारणों की पहचान करना और उनसे प्रभावित हंग से निपटने के लिए सरकार को ठोस सुझाव देना है।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर को इस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों में देश के वर्तमान जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएसएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि शामिल हैं, जबकि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी-1) को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

## मोदी-ट्रंप मुलाकात से पहले कांग्रेस ने अमेरिकी नीति और व्यापार समझौते पर जताई चिंता

नई दिल्ली, 14 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 17 जून को फ्रांस में प्रस्तावित मुलाकात से पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार से भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि भारत को ओमान तट के निकट अमेरिकी कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते तथा अमेरिकी प्रशासन के हालिया रवैये जैसे विषयों पर अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए। कांग्रेस महासचिव

संपादकीय



# विकास के अगले चरण की आवश्यकता

**भा**रत की लोकतांत्रिक एवं आर्थिक यात्रा में 10 जून, 2026 की तिथि एक मील के पथर के रूप में अंकित हुई। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, जब निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा हो गया। उद्योग जगत के लिए यह और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नेतृत्व की निरंतरता, नीतिगत स्थिरता और अर्थव्यवस्था की दिशा के प्रति विश्वास जैसे भाव समाहित हैं।

यही वे आधार हैं जिन पर निवेश एवं उद्यम की नींव टिकी होती है। उद्योग जगत के लिए ये 12 वर्ष स्वतंत्र भारत के सबसे अहम वर्षों में रहे। इस दौरान मोदी सरकार ने न केवल महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे के विकास को साकार रूप दिया है, बल्कि नीतियों को इस प्रकार से आकार दिया, जिससे भारत एक अधिक एकिकृत, अधिक डिजिटल और अधिक प्रतिस्पर्धी आर्थिक बन गया है।

इन 12 वर्षों की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ जीएसटी के माध्यम से एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण का रहा। राज्य स्तर पर विभिन्न अवरोधों को दूर करते हुए जीएसटी ने कंपनियों को लाजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने और बाजार में तेजी से पहुंचने में सक्षम बनाया। जीएसटी के साथ दिवालीयोजना एवं ऋण शोधन सहित न केवल बाजारों में अपेक्षित अनुशासन का संचार किया। इसने उधारी के तंत्र को मजबूत किया, वसूली की प्रक्रिया में सुधार किया और आश्वासन दिया कि भारत फंसी हुई परिसंपत्तियों के परिदृश्य को सुव्यवस्थित नियमों के माध्यम से सुलझाने के प्रति गंभीर है।

बुनियादी ढांचा इस कार्यकाल का दूसरा प्रमुख स्तंभ रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में असाधारण प्रगति की है। राजमार्गों का विस्तार द्रुत गति से हुआ है। रेल लाइनों का व्यापक विद्युतीकरण किया गया है। माल ढुलाई गलियारों का विस्तार हुआ। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

कम लाजिस्टिक्स लागत, तेजी से माल ढुलाई, छोटे शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी और बिजली की निर्बाध बंधन भरोसेमंद आपूर्ति जैसे पहलु व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये पहलु स्थायी विकल्पों की बात जोह रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभारने में मददगार बनते हैं। बुनियादी ढांचे पर यह जोर विनिर्माण आकांक्षाओं को भी परवान चढ़ाता है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं और संबंधित नीतिगत पहलों के माध्यम से भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, आटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और खास विनिर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। उद्योग जगत ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। घरेलू और विदेशी निवेश ने उन क्षेत्रों में भी गति पकड़ी है, जिनमें पहले भारत पर बहुत दांव नहीं लगाया जाता था।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि, भारत के एक प्रमुख स्मार्टफोन उत्पादक के रूप में उभरना और प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का आगे बढ़ना इस बड़े बदलाव का ही प्रतीक है। इसके चलते अब भारत को विनिर्माण और नवाचार के एक उदीयमान गढ़ के रूप में देखा जा रहा है। आज कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पुनर्विचार कर रही हैं। सोर्सिंग रणनीतियों में विविधता ला रही हैं और स्थायित्व से परिपूर्ण ऐसे क्षेत्राधिकारों की राह तलाश रही हैं, जहां वे दीर्घकालिक निवेश कर सकें।

ऐसे माहौल में भारत का विशाल आकार, प्रतिभाओं की भरमार, लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वरूप और सुधारों की गति उसे एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करते हैं, लेकिन केवल सही स्थिति में ही ही पर्याप्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण स्पष्ट संकेत रहा कि सरकार दृढ़ता से निर्णय लेने, समय के साथ सुधारों की निरंतरता बनाए रखने और अपनी नीतिगत मंशा को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्योग जगत के लिए यह विश्वसनीयता बेहद मूल्यवान है। यह अनिश्चितता को कम करती है और दीर्घकालिक पूंजी निवेश की संभावनाओं को और सुदृढ़ बनाती है।

औद्योगिक विकास पर सामाजिक और आर्थिक समावेशन का व्यापक प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली, आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल पहलों ने औपचारिक अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के साथ घरेलू स्थिरता में सुधार किया है। जब अधिक नागरिक बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सेवाओं से जुड़ते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ने और अपनी नीतिगत मंशा को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्योग जगत के लिए यह विश्वसनीयता बेहद मूल्यवान है। यह अनिश्चितता को कम करती है और दीर्घकालिक पूंजी निवेश की संभावनाओं को और सुदृढ़ बनाती है।

औद्योगिक विकास पर सामाजिक और आर्थिक समावेशन का व्यापक प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली, आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल पहलों ने औपचारिक अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के साथ घरेलू स्थिरता में सुधार किया है। जब अधिक नागरिक बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सेवाओं से जुड़ते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ने और अपनी नीतिगत मंशा को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्योग जगत के लिए यह विश्वसनीयता बेहद मूल्यवान है। यह अनिश्चितता को कम करती है और दीर्घकालिक पूंजी निवेश की संभावनाओं को और सुदृढ़ बनाती है।

## मोहब्बत रूठ जाए, तो जिंदगी के सारे रंग उड़ जाते हैं...

डॉ. मुफ्ताक अहमद शाह सहज हदा, मध्य प्रदेश

यह कहानी किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जिसने मोहब्बत में सिर्फ पाना नहीं, बल्कि खुद को खोना सीखा है। यह दास्तान है एहसास-ए-तनहई, हिज्र की कसक, और उन अंधेरों खूबियों की जो आंखों में ही हम तोड़ गए। जिंदगी कभी-कभी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का हर रास्ता धुंधला और पीछे का हर मजबूत मिट्टी का ढेर नजर आता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी को रंगीन बना देती है, लेकिन कोई यह क्यों नहीं बताता कि जब वह मोहब्बत रूठ जाए, तो जिंदगी के सारे रंग उड़ जाते हैं और सिर्फ एक ही रंग बचता है...

तनहई का स्याह रंग। जिस दिन वह मुझे छोड़कर गई, आसमान पर बादल तो नहीं थे, मगर मेरी आंखों में बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हिज्र का दर्द क्या होता है, यह मुझे उस रात मालूम हुआ जब घर की हर दीवार मुझ पर हंस रही थी और कम्परे का हर कोना उसकी मौजूदगी का पता पूछ रहा था। जुदाई तो सिर्फ एक लफ्ज था मेरे लिए, मगर जब गुजरी तो मालूम हुआ कि यह तो एक जिंदा दरगार होने का नाम है। हमने मिलकर कितने खूबियां बना बने थे, एक छोटा सा घर, शाम की चाय, और ढेर सारी बातें मगर वह सारे खूबियां अब मेरी आंखों में कांच के टुकड़ों की तरह चुभते हैं और जब भी आंखें बंद करता हूं, वही अंधेरे खूबियां सामने आ खड़े होते हैं और पूछते हैं कि हमारा क्या क्रमूर था? अब हालत यह है कि सुबह होती है तो जागने की कोई वजह नहीं होती, शाम खलती है तो दिल का दर्द और गहरा हो जाता है और रात को जब दुनिया सो जाती है, तो मेरे अंधेरे खूबियां जाग उठते हैं। लोग कहते हैं वक के साथ हर जूझ भर जाता है, लेकिन मेरा जूझ तो वक के साथ और हरा होता जा रहा था और मेरे दिल और दिमाग पर अब उसकी यादों का मुस्तकिल बसेरा था। वह उसका हल्के से मुसकुना, वह गुस्से में मुंह फेर लेना, और वह जाते-जाते आंखों की मुझकर देवना यह सब यादें अब मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी हैं और मैं चाहूं भी तो इनसे फुार मुमकिन नहीं क्योंकि यह यादें कोई मेहमान नहीं जो आए और चली जाएं, यह तो अब इस वीरान दिल की मालकिन बन बैठी हैं। आज भी जब बाहर तेज हवा चलती है या बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक देती हैं, तो दिल धड़क उठता है कि शायद वह लौट आई हों, मगर फिर तनहई का अहसास मुझे झंझोड़ कर कहता है कि वह जा चुकी है, और अब सिर्फ तुम हो, गुस्सारा हिज्र जब है, यह कभी न खत्म होने वाला दर्द है, इसलिए जिंदगी रूठ रही है, ससैंस आ जा रही है, मगर रूकीकत यही है कि मैं जी नहीं रहा, बस वक काट रहा हूं। सालों-साल गुजर गए, यादों का वह गुबार अब मेरे चेहरे की झुर्रियों और बालों की सफेदी में झलकने लगा था और दिल ने मान लिया था कि तनहई ही मेरा मुफ्फर है।

# विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर आज विशेष जीवन्मभर सहाय देने वाले क्यों झेल रहे हैं उपेक्षा?



योगेश कुमार गोयल नजफकगढ़ नई दिल्ली

## बोझ नहीं, घर की नींव हैं बुजुर्ग

प्रतिबंध 15 जून को विश्वभर में 'विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस' मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन्हें जागरूक करना और इसे रोकने के प्रयास करना है। वर्ष 2026 में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का वैश्विक विषय है 'जागरूकता से परे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम को कारण बनाना'। इस विषय का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता को ठोस कार्रवाई योग्य नीतियों में बदलना और ऐसे मजबूत, सुरक्षात्मक तंत्र सुनिश्चित करना है जो बुजुर्गों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्गों को अनुभवों की खान माना जाता रहा है लेकिन चिंतनगत स्थिति यह है कि हमारे यहां भी अब बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं। भारत में संयुक्त

परिवारों के बजाय आधुनिक युग में एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण भी बुजुर्गों की उपेक्षा के मामलों में वृद्धि हो रही है। आज की आधुनिक दुनिया में बुजुर्गों के साथ ऐसे बर्ताव के बढ़ते मामलों के पीछे सोशल स्टेटस भी प्रमुख वजह माना जाता है। दरअसल समाज में स्वयं की हैसियत बड़ी दिखाने की चाहत में कुछ लोगों को अपने ही परिवार के बुजुर्गों मार्ग की बड़ी रूकावट लगने लगते हैं। ऐसी ही रूढ़िवादी सोच के कारण उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक में अब वृद्धजनों के प्रति स्रेह की भावना कम हो रही है। बुजुर्गों की उपेक्षा के मामले हालांकि केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि विदेशों में तो बुजुर्गों की हालत और भी बुरी है लेकिन भारत के संदर्भ में यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में सदैव संयुक्त परिवार को अहमियत दी जाती रही है, जहां बुजुर्गों का सर्वोपरि स्थान रहा है। हमारे यहां दादा-दादी, माता-पिता, ताऊ-ताई, चाचा-चाची तथा कई बच्चों के साथ भरा-पूरा परिवार होता था, परिवार में बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार दिया जाता था लेकिन आज के बदलते दौर में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की धारणा खोती जा रही है, जिसके कारण लोग जहां अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी दादा-दादी, नाना-नानी के प्यार से वंचित हो रहे हैं। अकेले रहने के कारण जहां अब बुजुर्गों के प्रति अपराध बढ़ने लगे हैं, वहीं छोटे परिवारों में बच्चों को परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनकी कार्यशीलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दुनियाभर में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ



होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने और वृद्धजनों के प्रति उदारता तथा उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के अलावा उनकी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार को धारणा खोती जा रही है, जिसके कारण लोग जहां अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी दादा-दादी, नाना-नानी के प्यार से वंचित हो रहे हैं। अकेले रहने के कारण जहां अब बुजुर्गों के प्रति अपराध बढ़ने लगे हैं, वहीं छोटे परिवारों में बच्चों को परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनकी कार्यशीलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दुनियाभर में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने और वृद्धजनों के प्रति उदारता तथा उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के अलावा उनकी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार को धारणा खोती जा रही है, जिसके कारण लोग जहां अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी दादा-दादी, नाना-नानी के प्यार से वंचित हो रहे हैं। अकेले रहने के कारण जहां अब बुजुर्गों के प्रति अपराध बढ़ने लगे हैं, वहीं छोटे परिवारों में बच्चों को परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनकी कार्यशीलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में दुनियाभर में वृद्धों एवं प्रौढ़ों के साथ

भी बढ़ रही हैं। आईआईटी मद्रास ने बुजुर्गों के हेल्थ केयर पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट 'ग्लो बलाइजेशन और स्वास्थ्य' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों में मधुमेह, रक्तचाप तथा हृदय संबंधी बीमारियां ज्यादा आम मौजूद मिलीं। चौंकाने वाला यह तथ्य भी सामने आया कि केवल 18.9 प्रतिशत बुजुर्गों के पास ही स्वास्थ्य बीमा की सुविधा थी और स्वास्थ्य पर उनके ज्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं थी। बुजुर्गों की स्थिति पर आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की 27.5 फीसद आबादी गतिहीन है और बुजुर्गों की करीब 70 फीसद संख्या आर्थिक या पूरी तरह से दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर है।

बहरहाल, बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाज को संजीदा होने और विपरीत परिस्थितियों में उनका संबल बनकर उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए सकारात्मक माहौल उपलब्ध करने की दरकार है। वृद्धावस्था में बुजुर्ग शारीरिक रूप से शिथिल भी हो जाएं तो परिजनों का कर्तव्य है कि पूरे सम्मान के साथ उनका ध्यान रखा जाए। दरअसल जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र कमजोर होने लगता है और व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां चपेट में ले लेती हैं। वृद्धावस्था में विभिन्न बीमारियों के अलावा आमतौर पर घुटनों तथा जोड़ों में दर्द तथा रीढ़ की हड्डी के मुड़ने जैसी समस्याओं सहित शारीरिक स्थिति में बदलाव आना सामान्य बात है। बुजुर्गों को इस तरह की समस्याओं से राहत के लिए उन्हें उचित पोषण मिलना बेहद जरूरी है।

# बुजुर्ग के लिए अपमान, अब जमाना बदल गया संस्कारविहीन होता परिवार



संजय गोस्वामी, दुंदी बाजारपटना, बिहार

आज नए जमाने में बुजुर्ग की उपेक्षा की हो रही है उपेक्षा का अर्थ किसी बात, व्यक्ति या परिस्थिति को नजरअंदाज करना, ध्यान न देना या महत्व न समझना है इसे बोल चाल में लापरवाही अनादर या लिरकारण भी कहा जाता है आज के जमाने में, पैसे की बढ़ती अहमियत ने लोगों को इसे कमाने में इतना बिजी कर दिया है कि उनके पास दूसरों पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की वैल्यू तभी तक करते हैं जब तक उनके पास पैसा होता है, एक बार पैसा खत्म हो जाने पर, बुजुर्गों की अहमियत खत्म हो जाती है और उन्हें सिर्फ बोझ समझा जाता है। अपना फायदा नई पीढ़ी ज्यादा सेल्फिश होती जा रही है। वे ज्यादातर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों की देखभाल तभी करते हैं जब उन्हें विरासत में पैसा या प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद दिखती है; वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अपने बुजुर्गों के प्रति सच्चा, दया और त्याग की भावना कम होती जा रही है, क्योंकि वे बुजुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी को अपनी आजादी में रूकावट मानते हैं। नतीजतन, वे अपने फायदे के लिए बुजुर्गों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों की परेशानियां बुढ़ापे को जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता है—एक ऐसा पड़ाव जो अक्सर मुश्किलों से घिरा होता है—क्योंकि बुजुर्गों कई मुश्किलों से घिरे होते हैं जिनकी वजह से वे दूसरों के साथ समाज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नई पीढ़ी पारंपरिक विचारों वाले लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना सही नहीं समझती, नतीजतन, युवा बुजुर्गों के अनुभवों और नजरिए को नजरअंदाज करते लगते हैं। बुजुर्गों को होने वाली परेशानियां ज्यादा साफ होती जा रही हैं, जबकि समाज में उनकी उपयोगिता कम होती दिख रही है। इन समस्याओं को इस तरह बताया जा सकता है... **शारीरिक चुनौतियाँ** - बुढ़ापे जिंदगी का आखिरी दौर होता है, एक ऐसा समय जब शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। इस दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालते हैं और कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। जहाँ कुछ लोग साठ साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं, वहीं दूसरों को उम्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना

पड़ता है, कुल मिलाकर, बुजुर्गों को बढ़ती मुश्किलों और समाज में उनकी अहमियत में कमी का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापे जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, एक ऐसा समय जो अक्सर शारीरिक कमजोरी और काम करने की कम क्षमता से पहचाना जाता है। गुजार्ने के लिए दूसरों पर निर्भर होना जरूरी हो जाता है, और यही निर्भरता बुजुर्गों की परेशानियों की जड़ होती है। उन्हें अक्सर शारीरिक और आर्थिक रूप से घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चाहे वे पढ़े-लिखे हों या अनपढ़, उच्च समय उनकी जिंदगी अक्सर अस्थिर हो जाती है; उन्हें नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आती है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक असुविधा झेलता है, और अक्सर आर्थिक परेशानियों का एक हिस्सा पाता है कि नई पीढ़ी उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देती। इंसानियत तरकी के रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। बदलाव कुदरत का एक बुनियादी नियम है, लेकिन इंसानों ने अपनी दिमागी काबिलियत से भी बदलाव को आगे बढ़ाया है। नई सुविधाओं की लगातार तलाश इस तरकी की चाहत को और बढ़ाती है। आज, इंसायनियत तरकी के साथ पैसा होता है, एक बार पैसा खत्म हो जाने पर, बुजुर्गों की अहमियत खत्म हो जाती है और उन्हें सिर्फ बोझ समझा जाता है। अपना फायदा नई पीढ़ी ज्यादा सेल्फिश होती जा रही है। वे ज्यादातर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों की देखभाल तभी करते हैं जब उन्हें विरासत में पैसा या प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद दिखती है; वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अपने बुजुर्गों के प्रति सच्चा, दया और त्याग की भावना कम होती जा रही है, क्योंकि वे बुजुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी को अपनी आजादी में रूकावट मानते हैं। नतीजतन, वे अपने फायदे के लिए बुजुर्गों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों की परेशानियां बुढ़ापे को जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता है—एक ऐसा पड़ाव जो अक्सर मुश्किलों से घिरा होता है—क्योंकि बुजुर्गों कई मुश्किलों से घिरे होते हैं जिनकी वजह से वे दूसरों के साथ समाज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नई पीढ़ी पारंपरिक विचारों वाले लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना सही नहीं समझती, नतीजतन, युवा बुजुर्गों के अनुभवों और नजरिए को नजरअंदाज करते लगते हैं। बुजुर्गों को होने वाली परेशानियां ज्यादा साफ होती जा रही हैं, जबकि समाज में उनकी उपयोगिता कम होती दिख रही है। इन समस्याओं को इस तरह बताया जा सकता है... **शारीरिक चुनौतियाँ** - बुढ़ापे जिंदगी का आखिरी दौर होता है, एक ऐसा समय जब शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। इस दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालते हैं और कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। जहाँ कुछ लोग साठ साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं, वहीं दूसरों को उम्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना



प्राते हैं। पिछली सदी में इंसानी समाज ने बहुत तरकी की है। सिर्फ सौ साल में, इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं—जैसे रेडियो, कार, टेली विज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, बस, मोबाइल फोन और एंटीबिोटिक्स आदि—जो अब हमारी पाता है कि नई पीढ़ी उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देती। इंसानियत तरकी के रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। बदलाव कुदरत का एक बुनियादी नियम है, लेकिन इंसानों ने अपनी दिमागी काबिलियत से भी बदलाव को आगे बढ़ाया है। नई सुविधाओं की लगातार तलाश इस तरकी की चाहत को और बढ़ाती है। आज, इंसायनियत तरकी के साथ पैसा होता है, एक बार पैसा खत्म हो जाने पर, बुजुर्गों की अहमियत खत्म हो जाती है और उन्हें सिर्फ बोझ समझा जाता है। अपना फायदा नई पीढ़ी ज्यादा सेल्फिश होती जा रही है। वे ज्यादातर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों की देखभाल तभी करते हैं जब उन्हें विरासत में पैसा या प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद दिखती है; वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अपने बुजुर्गों के प्रति सच्चा, दया और त्याग की भावना कम होती जा रही है, क्योंकि वे बुजुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी को अपनी आजादी में रूकावट मानते हैं। नतीजतन, वे अपने फायदे के लिए बुजुर्गों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों की परेशानियां बुढ़ापे को जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता है—एक ऐसा पड़ाव जो अक्सर मुश्किलों से घिरा होता है—क्योंकि बुजुर्गों कई मुश्किलों से घिरे होते हैं जिनकी वजह से वे दूसरों के साथ समाज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नई पीढ़ी पारंपरिक विचारों वाले लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना सही नहीं समझती, नतीजतन, युवा बुजुर्गों के अनुभवों और नजरिए को नजरअंदाज करते लगते हैं। बुजुर्गों को होने वाली परेशानियां ज्यादा साफ होती जा रही हैं, जबकि समाज में उनकी उपयोगिता कम होती दिख रही है। इन समस्याओं को इस तरह बताया जा सकता है... **शारीरिक चुनौतियाँ** - बुढ़ापे जिंदगी का आखिरी दौर होता है, एक ऐसा समय जब शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। इस दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालते हैं और कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। जहाँ कुछ लोग साठ साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं, वहीं दूसरों को उम्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना

दिया है। बुजुर्ग अक्सर नई पीढ़ी के काम करने के तरीके से परेशान रहते हैं, वे अपने बच्चों को बेपरवाह और लापरवाह समझते हैं, काम करने और जीने के नए तरीके उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते। वे अपने समय को सही ठहरते हैं। आज हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव होता है। दश तेजी से सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे बुजुर्गों को होने वाली समस्याएँ खतरनाक रूप ले रही हैं। इसके मुख्य कारणों में घटती मरुद दर और ग्रुपीय और अंतर्ग्रुपीय दोनों स्तरों पर आबादी के डयनामिक्स में बदलाव शामिल है। हम तेजी से जनसांख्यिकीय अस्तित्वन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ बुजुर्गों की आबादी के गैर-उत्पादक हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जन्म दरें उपादक कर्मचारियों की संख्या से आगे निकल जायें। 21वीं सदी में बुजुर्गों की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि और लैटेंट आदि—जो अब हमारी पाता है कि नई पीढ़ी उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देती। इंसानियत तरकी के रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। बदलाव कुदरत का एक बुनियादी नियम है, लेकिन इंसानों ने अपनी दिमागी काबिलियत से भी बदलाव को आगे बढ़ाया है। नई सुविधाओं की लगातार तलाश इस तरकी की चाहत को और बढ़ाती है। आज, इंसायनियत तरकी के साथ पैसा होता है, एक बार पैसा खत्म हो जाने पर, बुजुर्गों की अहमियत खत्म हो जाती है और उन्हें सिर्फ बोझ समझा जाता है। अपना फायदा नई पीढ़ी ज्यादा सेल्फिश होती जा रही है। वे ज्यादातर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों की देखभाल तभी करते हैं जब उन्हें विरासत में पैसा या प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद दिखती है; वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अपने बुजुर्गों के प्रति सच्चा, दया और त्याग की भावना कम होती जा रही है, क्योंकि वे बुजुर्गों की देखभाल करने की जिम्मेदारी को अपनी आजादी में रूकावट मानते हैं। नतीजतन, वे अपने फायदे के लिए बुजुर्गों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुजुर्गों की परेशानियां बुढ़ापे को जिंदगी का आखिरी पड़ाव माना जाता है—एक ऐसा पड़ाव जो अक्सर मुश्किलों से घिरा होता है—क्योंकि बुजुर्गों कई मुश्किलों से घिरे होते हैं जिनकी वजह से वे दूसरों के साथ समाज में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नई पीढ़ी पारंपरिक विचारों वाले लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना सही नहीं समझती, नतीजतन, युवा बुजुर्गों के अनुभवों और नजरिए को नजरअंदाज करते लगते हैं। बुजुर्गों को होने वाली परेशानियां ज्यादा साफ होती जा रही हैं, जबकि समाज में उनकी उपयोगिता कम होती दिख रही है। इन समस्याओं को इस तरह बताया जा सकता है... **शारीरिक चुनौतियाँ** - बुढ़ापे जिंदगी का आखिरी दौर होता है, एक ऐसा समय जब शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। इस दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डालते हैं और कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। जहाँ कुछ लोग साठ साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं, वहीं दूसरों को उम्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना



कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी इन्डौर, मध्यप्रदेश

मन के मुसाफिर भोले भरे, यहां-वहां मंशरते हैं, प्रेम से जब-जब बोली भोले, भोले वहां आ जाते हैं। मन के मुसाफिर ... मन की कुटिया में रहते भोले, मन बीन बजाते रहते हैं, भक्ति के पथ पर जो चल दें, भोले उसकें हो जाते हैं। मन के मुसाफिर ... समय की धारा से छितरकर, जो भोले में रम जाता है, भोले खुद मन पर आकर, मन भर खुशियां भर जाते हैं। मन के मुसाफिर ... आओ भोले के शब्दों से, मन की सींचें हर एक क्यारी, भर नहीं हो मन पर कोई, बस भोले से रहे उधारी। मन के मुसाफिर ...

**सूचना**  
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।  
-सम्पादक

## शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नवगठित कार्यकारणी की बैठक



-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नवगठित कार्यकारणी की प्रथम बैठक पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता एवं मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कांग्रेस के उदयपुर संकल्प के अनुसार गठित 31 सदस्यीय कमेटी में 1 कोषाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 10 सचिव एवं 5 कार्यकारणी सदस्य हैं। नवगठित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 65 प्रतिशत सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। नवगठित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का परिचय अम्बिकापुर शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल ने कराया। इस दौरान आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने नवगठित कार्यकारणी सदस्यों को बधाई देते हुए उन्हें अपने बूध और उत्सर्ग मौजूद अनुभाग में सूझता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकारणी सदस्यों को कहा कि हम प्रत्येक माह अपने कार्य परिणामों की रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने ब्लॉक कार्यकारणी सदस्यों के प्रभार के विवरण हेतु ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में शहरी क्षेत्र में विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। भाजपा सिस्टम का उपयोग कर शहरी क्षेत्र में खेल करने में माहिर है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन के पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि किसी भी इमारत की मजबूती उसके नीचे पर आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार से चुनावी इमारत की मजबूती बूध की मजबूती पर आधारित होता है। प्रदेश महामंत्री जेपी श्रीवास्तव ने कार्यकारणी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले चुनाव को जीतने के लिए सत्तापक्ष साम-दाम-दंड-भेद सब अपनाएगा, इससे निपटने का एकमात्र तरीका मतदाताओं से सतत संपर्क होगा। इस दौरान पूर्व महापौर डॉ अजय तिवारी, मो.इस्लाम, हेमंत सिन्हा, विनय शर्मा, जीवन यादव, अमित सिंह, शंकर प्रजापति, गुरुप्रति सिसु, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, सतीश बारी, निकी खान, सोहन जायसवाल, मेराज रंगेश, विकास शर्मा, शांका चौधरी, पवन सिंह, आलोक गुप्ता, अमित वर्मा, बनाफर केरकेट्टा, रोशन कर्नौजिया, धनमीत छावड़ा, शंकर लाल सिंह, उषेंद्र विश्वकर्मा रूबी जैन, शकीला सिद्दीकी, विजय बेक, मनोज तिवारी सहित ब्लॉक कार्यकारणी के सदस्य मौजूद रहे।

## जुआ खेलते 12 पकड़ाए, 6 हजार 720 रुपए जब्त

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली पुलिस जुआ खेलते 12 जुआरियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। 13 जून को कोतवाली पुलिस के मुखबिर से जानकारी मिली की नमनाकला स्थित गुडलक गेज के पीछे सार्वजनिक स्थल पर बैठकर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने जुआडियों के फंड से 52 पते ताश व 6 हजार 720 रुपए जब्त किया है। मौके से अनिल कश्यप निवासी गंगापूर, रमेश सेमरिया निवासी परसोडीखुर्द, सहायगुन निवासी नमनाकला, संतोष कुमार निवासी नमनाकला, अनुज जायसवाल निवासी घुट्टारारा, पवन साहनी निवासी नमनाकला, असोम तिवारी निवासी मुक्तिपारा, विरेन्द्र एका निवासी दर्रापारा, मनोज सोनकर निवासी नमनाकला, दीपक सोनकर निवासी खट्टीकारा, सदाचम हुसैन निवासी पानी टकी के पास नमनाकला व नानेन्द्र सोनकर, कार्मेल स्कूल के गेट के पास नमनाकला के खिलाफ पुलिस ने धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।



# जमीन विवाद में बुजुर्ग किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या

## विवादित भूमि की जुताई को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 8 आरोपी गिरफ्तार...

राजस्व न्यायालय में भी चल रहा है मामला...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

बत्तीली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ग्राम सिलमा निवासी 57 वर्षीय किसान होस राम पैकरा की विवादित जमीन पर हुए विवाद के दौरान ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार सुबह करीब 11.30 बजे की है। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम सिलमा निवासी होस राम पैकरा और ग्राम थपई निवासी बजरंग पैकरा के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवादित भूमि लालमाटी क्षेत्र में स्थित है। दोनों पक्ष उक्त जमीन पर अपना-अपना दावा कर रहे थे। करीब दो माह पूर्व भी इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीत हुई थी।



रविवार को बजरंग पैकरा का बेटा ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन की जुताई करने पहुंचा था। उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलने पर होस राम पैकरा अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे और जुताई का विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि बजरंग पैकरा और उसके परिवार के लोगों ने होस

राम तथा उनके परिजनों की लाठी-डंडों से पीटाई कर दी। मारपीट के दौरान जमीन पर गिरे होस राम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर बत्तीली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने दबिश देकर मामले में



वसीयतनामा को लेकर भी है विवाद...

जानकारी के अनुसार विवादित भूमि कामेश्वरी नामक महिला के नाम दर्ज थी। महिला निःसंतान थी और उसकी देखरेख धनेश्वरी करती थी। इसी आधार पर भूमि का वसीयतनामा धनेश्वरी के पक्ष में किए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरा पक्ष भी जमीन पर अपना अधिकार जता रहा है। भूमि संबंधी मामला वर्तमान में राजस्व न्यायालय में विचारार्थ है। इसी विवाद के बीच हत्या की यह वाददात सामने आई।

भुवनेश्वर, बजरंग, उमेश, मनोज, रघुनंदन, ललित। पुलिस के अनुसार घटना के समय बांधन, कमली और प्यारी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर उमेश चला रहा था।

## वन भूमि से 17 अवैध मकान हटाए, बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप... तकिया पावर हाउस के पास वन विभाग की कार्रवाई अतिक्रमणकारियों ने कहा... 20-30 वर्षों से रह रहे थे



भाजपा कांग्रेस नेताओं के वयान भी आए सामने...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर से लगे ग्राम पंचायत तकिया स्थित पावर हाउस के पास वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ रविवार सुबह वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में वन विभाग की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और चिह्नित 17 अवैध मकानों को हटाकर



भाजपा पार्षद ने टी लफाई...

भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि उन पर एक मंत्र विशेष को मिशाना बनाकर अतिक्रमण हटाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि तकिया में हुई कार्रवाई को देखकर स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले में हाईकोर्ट ने 2 अपील को प्रशासन और वन विभाग को जांच कर 60 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया कि अतिक्रमण पुराना नहीं है और संबंधित लोग वन भूमि चूका के पात्र नहीं हैं। इसके आधार पर कार्रवाई की गई है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल...

कांग्रेस के पूर्व पार्षद दीपक मिश्रा ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई परिवार 30 से 40 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उनका कहना है कि क्षेत्र के लोग सांसद और विधायक से भी मिले थे, जहां उन्हें आशवासन दिया गया था कि उनके मकान नहीं टूटेंगे। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में प्रभावित परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है।

## जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए देशभर में जागरूकता अभियान

### दिल्ली समागम में गूजी जनजातीय स्वाभिमान की आवाज...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

जनजाति सुरक्षा मंच ने रविवार को उरांव समाज भवन, पटेलनगर में प्रेस वार्ता आयोजित कर दिल्ली में आयोजित जनजाति समागम 2026 की जानकारी दी। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा, आस्था और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 24 मई को नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में विशाल जनजाति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के विभिन्न जनजातीय समुदायों के लाखों लोगों ने भागीदारी की। प्रेस वार्ता में मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेशराम भगत, प्रांत संयोजक रोशन प्रजापति सिंह, सह संयोजक इंद्र भगत, जिला संयोजक बिबरीलाल उरांव, जिला संरक्षक नाथराम भगत, खंड संयोजक खेमराज सिंह तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित इस समागम में देश के 500 से अधिक जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पारंपरिक वेपथुभा, लोकनृत्य, लोकगीत, मांदर-डोल और अन्य सांस्कृतिक प्रतियों के माध्यम से जनजातीय समाज ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। लाल किला मैदान में आयोजित



कार्यक्रम को जनजातीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया गया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से भी लगभग 5 हजार लोग इस आयोजन में शामिल हुए। अम्बिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायगढ़, कोरबा और जशपुर सहित विभिन्न जिलों से समाज के प्रतिनिधि, युवा, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। सरगुजा संभाग की भागीदारी ने राष्ट्रीय मंच पर क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति और सामाजिक एकता की मजबूत पहचान प्रस्तुत की। मंच के अनुसार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में जनजातीय समाज की परंपराओं, प्रकृति-पूजा, जल-जंगल-जमीन से जुड़े जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को भारत की आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। साथ ही कहा कि जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति और मानव जीवन के

बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेस वार्ता में मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि जनजातीय समाज केवल प्रकृति का संरक्षक नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना का जीवंत स्वरूप है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय चिंताओं से जूझ रही है, तब यह जनजातीय जीवन-दर्शन टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है।

जनजातीय पहचान से जुड़े मुद्दों पर उठाई मांग : मंच ने कहा कि जनजातीय समाज की पहचान केवल संवैधानिक सूची का विषय नहीं है, बल्कि उसकी आस्था, संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज और सामाजिक जीवन-पद्धति से भी जुड़ी हुई है। मंच ने मांग की कि अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट वैधानिक परिभाषा निर्धारित की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस विषय को लेकर पिछले दो दशकों से देशभर में

जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 26 राज्यों के हजारों गांवों में हस्ताक्षर अभियान चलकर लाखों लोगों का समर्थन जुटाया गया था। इसके बाद विभिन्न स्तरों पर रैलियां, समेलन, जनसंघर्ष अभियान तथा जनप्रतिनिधियों से संवाद के माध्यम से यह मुद्दा लगातार उठया जाता रहा है।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी हुई मुलाकात...

मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि 28 मई 2026 को संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा तथा संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मंच ने कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक अस्मिता, परंपरागत जीवन-पद्धति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने चाहिए। यह केवल आरक्षण या कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों जनजातीय लोगों की पहचान, परंपरा और अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। प्रेस वार्ता के अंत में मंच के पदाधिकारियों ने जनजातीय समाज से एकजुट होकर अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया।

## स्वदेशी ही आत्मनिर्भर भारत का आधार

### प्रांतीय विचार वर्ग में गूजा स्वावलंबन का संदेश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में अम्बिकापुर में आयोजित प्रांतीय विचार वर्ग एवं कार्यशाला में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के विषय पर व्यापक मंचन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न संभागों से आए दायित्ववान कार्यकर्ता, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रांत स्तरीय कार्यकर्ता तथा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के पंचम सत्र में सरगुजा सांसद चितामणि महाराज, सरगुजा जिला संचालक भगवानदास बंसल, संत गणेश गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र लखपाल, प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं स्वदेशी चिंतक प्रो. अश्विनी महजन, क्षेत्रीय संयोजक सुधीर दाते, प्रांत संयोजक एवं स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक जगदीश पटेल तथा सुब्रत चाकी मंचासीन रहे। मुख्य वक्ता प्रो. अश्विनी महजन ने भारत की आर्थिक यात्रा, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और स्वदेशी आधारित विकास मॉडल पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत हजारों वर्षों तक विपन्न की अग्रणी अर्थव्यवस्था रहा है और आज भी उसके पास विशाल युवा शक्ति, बड़ा बाजार तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन ने भारत की आर्थिक संरचना को गहरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन देश पुनः वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रो. महजन ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत के भविष्य का आधार बताते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीक और नवाचार को अपनाए बिना भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़



सकता। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, यूपीआई और तकनीकी नवाचारों ने भारत को विश्व में नई पहचान दिलाई है। भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र आज विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुका है और देश के युवाओं में नई तकनीकों को अपनाने की अपार क्षमता है। उन्होंने आईटी नियंत्रण, डिजिटल करेंसी और तकनीकी उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। सांसद चितामणि महाराज, भगवानदास बंसल तथा कुलपति राजेंद्र लखपाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, 'चौकल फॉर लोकल' और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। सांसद चितामणि महाराज ने सरगुजा भाषा में संबोधन देते हुए कहा कि स्थानीय उद्योगों, कुटीर उद्यमों और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देकर भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। साथ ही वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग तथा रोजगार सृजन में स्वदेशी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। जगदीश पटेल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि भारत को विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी चिंतन, स्थानीय उत्पादन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। उन्होंने स्वावलंबी भारत अभियान की कार्ययोजनाओं और उद्देश्यों की जानकारी दी।

## राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान अंतिम चरण में, सरगुजा में मिली ऐतिहासिक और दुर्लभ पाण्डुलिपियां

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में संचालित राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अभियान का प्रथम चरण 15 जून को पूर्ण होने जा रहा है। इस दौरान सरगुजा जिले में प्राचीन ज्ञान-संपदा के रूप में अनेक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पाण्डुलिपियां सामने आ रही हैं। अभियान के अंतर्गत अम्बिकापुर नगर में दो संरक्षकों के पास महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियां प्राप्त हुई हैं।

डॉ. पाठक ने बताया कि यह पत्र स्वतंत्रता पूर्व का है, जिसे उनके बाबा जी द्वारा लिखा गया था। उल्लेखनीय है कि अम्बिकापुर नगर में वनदुर्गा से संबंधित कई पाण्डुलिपियां पूर्व में भी प्राप्त हो चुकी हैं। पाण्डुलिपियों का अवलोकन करते हुए नगर निगम आयुक्त श्री डी.एन. कश्यप ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हमारी समृद्ध प्राचीन ज्ञान-संपदा सामने आ रही है, जिसका लाभ वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को मिलेगा। सर्वेक्षण अभियान के दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल तथा जिला सदस्य श्रीश मिश्र भी उपस्थित रहे। श्रीमती अग्रवाल ने स्वयं पाण्डुलिपियों को पोटल पर अपलोड करने की प्रक्रिया में सहभागिता निभाई। इसी क्रम में बाबूपारा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेणुधर सिंह के पास महामया विजयोत्सव वंदना नामक एक महत्वपूर्ण पाण्डुलिपि प्राप्त हुई। इस पाण्डुलिपि में महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव एवं महाराज

रामानुज शरण सिंह देव बहादुर से संबंधित विरुदावली का उल्लेख मिलता है। हालांकि इसके लेखक एवं लेखन काल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अपलोडिंग प्रक्रिया के दौरान जिला सदस्य श्रीश मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक पूरे देश में एक करोड़ आठ लाख से अधिक पाण्डुलिपियों का सफलतापूर्वक जियो-टैगिंग किया जा चुका है। वहीं सरगुजा जिले में 13 करस्टोडियन के पास उपलब्ध 46 पाण्डुलिपियों को अब तक पोटल पर अपलोड किया जा चुका है। पाण्डुलिपियों के अपलोडिंग का कार्य सर्वेयर गौरव पाठक द्वारा नगर निगम आयुक्त श्री डी.एन. कश्यप एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शारदा अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। यह अभियान देश की अमूल्य सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।





# 24 साल का जुगाड़ तंत्र!

प्रतिनियुक्ति से शुरू हुई कहानी, संविलियन पर जाकर अटक गई

- मृत्यु महासंघ का कर्मचारी, कलेक्टर कार्यालय की कुर्सी और 24 साल की व्यवस्था**
- नियम हार गए, जुगाड़ जीत गया? चौबीस साल तक चलती रही प्रतिनियुक्ति की कहानी**
- प्रतिनियुक्ति की रजत जयंती, 24 साल तक चलता रहा सरकारी जुगाड़!**
- संविलियन नहीं हुआ, फिर भी नहीं टूटा संबंध! आखिर किसका था संरक्षण?**
- सेवा पुस्तिका खुली तो खुल गए राज! चौबीस साल की प्रतिनियुक्ति पर उठे सवाल**

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला - कोरिया



- कलेक्टर कार्यालय में 24 साल की पदस्थापना, नियमों से बड़ी थी व्यवस्था?**
- जुगाड़ एक्सप्रेस: वर्ष 2000 से 2024 तक दौड़ती रही प्रतिनियुक्ति की गाड़ी**
- कुर्सी वही, फाइल वही, कहानी वही! आखिर कैसे चलता रहा 24 साल का जुगाड़?**
- राजस्व विभाग में जगह नहीं मिली, फिर भी व्यवस्था नहीं टूटी!**
- 'अस्थायी' का स्थायी साम्राज्य! कोरिया की फाइलों से निकली 24 साल पुरानी कहानी**

मृत्यु महासंघ से कलेक्टर कार्यालय तक का ऐसा सफर, जिसे देखकर सरकारी नियम भी पूछ रहे होंगे— आखिर मैं किस काम का हूँ?

## संविलियन का सपना और नियमों की दीवार

दस्तावेजों और प्रशासनिक चर्चाओं से यह भी संकेत मिलता है कि राजस्व विभाग में संविलियन की संभावनाएं भी टटोली गईं, यदि यह सही है तो यह समझना कठिन नहीं कि लंबे समय तक किसी कार्यालय में कार्यरत रहने वाला कर्मचारी उसी व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहेगा, लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है, संविलियन का रास्ता आसान नहीं था, नियम सामने खड़े थे, परिणाम यह हुआ कि संविलियन संभव नहीं हो पाया, यहाँ से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जब संविलियन नहीं हो सकता था तो फिर व्यवस्था कैसे चलती रही? क्या हर बार प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला दिया गया? क्या हर बार कार्यालयीन मजबूरी का तर्क आगे आया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था ने नियमों से ज्यादा मजबूत जगह बना ली थी?

### फाइलों की भाषा में छिपे संकेत...

वर्ष 2020 के दस्तावेज विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं, इनमें जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि स्टैनोपाफर वर्ग-01 की आवश्यकता है और कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो सकते हैं, यह तर्क निश्चित रूप से महत्व रखता है, लेकिन प्रश्न यह भी है कि यदि आवश्यकता इतनी गंभीर थी तो वर्षों तक नियमित भर्ती, पदस्थापना या वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या पूरा जिला प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था पर निर्भर था जो मूल रूप से अस्थायी थी? यदि उत्तर 'हाँ' है तो यह प्रशासनिक कमजोरी का विषय है, यदि उत्तर 'नहीं' है तो फिर चौबीस वर्षों तक व्यवस्था जारी रखने का कारण क्या था?

### सेवा पुस्तिका ने खोल दी पुरानी अलमारी

वर्ष 2024 में जब सेवा पुस्तिका और निरंतरता प्रमाण पत्र की मांग सामने आई तो मानो वर्षों से बंद अलमारी का ताला खुल गया, सेवा पुस्तिका किसी कर्मचारी का सरकारी इतिहास होती है, उसमें दर्ज हर प्रविष्टि उसके करियर की कहानी कहती है, जब मूल विभाग ने सेवा पुस्तिका मांगी तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा कि आखिर इतने वर्षों तक सेवा संबंधी नियंत्रण की वास्तविक स्थिति क्या रही? क्या सभी अभिलेख समय पर अद्यतन हुए? क्या विभागीय अनुमतियाँ नियमित रूप से ली गईं? क्या प्रतिनियुक्ति की अवधि का समय-समय पर परीक्षण हुआ? क्या प्रशासनिक आदेशों की श्रृंखला पूरी तरह निरामसम्मत थी? इन सवालों का उत्तर रिकॉर्ड में होगा, लेकिन फिलहाल सवालों की संख्या उत्तरों से अधिक दिखाई देती है।



नियमों की किताबें एक तरफ, जुगाड़ की फाइलें दूसरी तरफ!

—रवि सिंह—  
कोरिया, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है कि फाइलों की अपनी एक जिंदगी होती है, कुछ फाइलें जन्म लेते ही धूल खा जाती हैं, कुछ वर्षों तक टेबलों पर भटकती रहती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो किसी सरकारी कर्मचारी से भी ज्यादा लंबी सेवा कर जाती हैं, कोरिया जिले से जो दस्तावेज दैनिक घटती-घटना के सामने आए हैं वह ऐसी ही कहानी को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जिसमें प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना, संविलियन, सेवा पुस्तिका और प्रशासनिक संरक्षण जैसे शब्द एक साथ दिखाई देते हैं।

यह कहानी किसी एक आदेश, एक कलेक्टर, एक विभाग या एक सरकार की नहीं है, यह कहानी लगभग चौबीस वर्षों तक फैली उस प्रशासनिक यात्रा की है, जिसमें एक अस्थायी व्यवस्था इतनी लंबी चली कि वह खुद स्थायी व्यवस्था जैसी दिखाई देने लगी, दस्तावेज बताते हैं कि वर्ष 2000

में मृत्यु महासंघ से जुड़े कर्मचारी घनश्याम प्रसाद मिश्रा को प्रतिनियुक्ति पर कलेक्टर कार्यालय कोरिया भेजा गया, सामान्य सरकारी समझ कहती है कि प्रतिनियुक्ति कुछ समय के लिए होती है, लेकिन यहाँ प्रतिनियुक्ति ने शायद कैलेंडर देखा ही बंद कर दिया, साल गुजरते गए, सरकारें बदलती रहीं, अधिकारी आते-जाते रहे, लेकिन व्यवस्था अपनी जगह बनी रही।

### प्रतिनियुक्ति या सरकारी अमरत्व?

यदि सरकारी सेवा नियमों पर कोई शोधाधी शोध करना चाहे तो उसे यह मामला अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रतिनियुक्ति ने वह उपलब्धि हासिल की दिखाई देती है जो सामान्य सरकारी कर्मचारी अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते, सवाल यह नहीं कि किसी कर्मचारी ने अच्छा काम किया या नहीं, सवाल यह है कि यदि प्रतिनियुक्ति अस्थायी थी तो वह चौबीस वर्षों तक कैसे चलती रही? यदि मूल विभाग मृत्यु महासंघ था तो प्रशासनिक नियंत्रण की अंतिम रेखा कहाँ खिंची हुई थी? यदि



कर्मचारी की आवश्यकता इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो नियमित वैधानिक समाधान क्यों नहीं खोजा गया? सरकारी व्यवस्था में अक्सर कहा जाता है कि नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन इस फाइल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि नियम एक तरफ खड़े होकर व्यवस्था को गुजरते हुए देख रहे थे और व्यवस्था मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी।

## सरकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी— 'चलने दो'

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक अनौपचारिक सिद्धांत वर्षों से जीवित है—चलने दो, यदि कोई व्यवस्था बिना विवाद के चल रही है तो उसे छोड़ने से बचो, यदि कोई फाइल वर्षों से एक ही तरीके से चल रही है तो उसे वैसे ही चलने दो, यदि कोई अस्थायी व्यवस्था स्थायी हो गई है तो उसे भी चलने दो, समस्या यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब कोई व्यवस्था नियमों के स्थान पर परंपरा के भरोसे चलने लगती है तो एक दिन वही परंपरा विवाद का विषय बन जाती है, कोरिया की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है, चौबीस वर्षों तक सब कुछ सामान्य लगता रहा, लेकिन जैसे ही पुराने दस्तावेज सामने आए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया—आखिर यह सब हुआ कैसे?

### सवाल जो अब भी जवाब मांग रहे हैं...

यदि प्रतिनियुक्ति अस्थायी थी तो उसकी अधिकतम अवधि कितनी थी? यदि संविलियन संभव नहीं था तो प्रयास किस आधार पर किए गए? यदि कर्मचारी मूल विभाग का था तो सेवा पुस्तिका इतने लंबे समय तक किस प्रशासनिक नियंत्रण में रही? यदि कार्यालय को वास्तव में कर्मचारी की आवश्यकता थी तो नियमित समाधान क्यों नहीं खोजा गया? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार था तो फिर चौबीस वर्षों तक एक ही व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती रही? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल भावनाओं या समर्थन-विरोध से नहीं बल्कि रिकॉर्ड और नियमों से ही दिया जा सकता है।

### फाइलों में दर्ज प्रशासनिक दर्शन

इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो फाइलें स्वयं कह रही हों कि सरकारी कार्यालयों में दो व्यवस्थाएँ साथ-साथ चलती हैं, एक वह जो नियम पुस्तिका में लिखी होती है और दूसरी वह जो व्यवहार में लागू होती है, नियम पुस्तिका कहती है प्रतिनियुक्ति अस्थायी है, व्यवहार कहता है जरूरत पड़ने पर यह पॉटियो पार कर सकती है, नियम पुस्तिका कहती है संविलियन के लिए प्रक्रिया है, व्यवहार कहता है प्रयास करते रहिए, शायद कभी रास्ता निकल आए, नियम पुस्तिका कहती है हर व्यवस्था का समयबद्ध परीक्षण होना चाहिए, व्यवहार कहता है—जब तक कोई सवाल न पूछे, सब ठीक है।

## चौबीस साल लंबी इस कहानी का अंतिम निष्कर्ष क्या होगा...

कोरिया जिले की यह फाइल अब केवल एक कर्मचारी की फाइल नहीं रह गई है, यह सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली, प्रतिनियुक्ति व्यवस्था, प्रशासनिक निर्णयों और वर्षों से चल रही परंपराओं का आईना बन चुकी है, चौबीस साल लंबी इस कहानी का अंतिम निष्कर्ष चाहे जो निकले, लेकिन इतना तय है कि इसमें एक बात फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी व्यवस्था नियमों से चलती है या फिर उन व्यवस्थाओं से, जो समय के साथ नियमों से भी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है।

## अब क्या होना चाहिए ?

इस पूरे मामले में सबसे आवश्यक चीज पारदर्शिता है, यदि सभी आदेश, प्रतिनियुक्तियाँ, अनुमतियाँ और सेवा संबंधी निर्णय नियमों के अनुरूप हुए हैं तो उन्हें सार्वजनिक परीक्षण से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कहीं प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हुई हैं तो उनकी समीक्षा भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि यह मामला एक कर्मचारी का नहीं है, यह उन सैकड़ों कर्मचारियों का भी प्रश्न है जो वर्षों से नियमों के अनुसार अपनी सेवा यात्रा पूरी कर रहे हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से लागू हो।

## मेडिकल कॉलेज मान्यता विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, बोले... 'कांग्रेस ज्यादा खुश न हो, मैच अभी बाकी है'

—संवाददाता—  
मनेंद्रगढ़, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।



नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) द्वारा छत्तीसगढ़ के पांच नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की खबर के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी कायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है, एमसीबी कलेक्टर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैच अभी बाकी है और राज्य सरकार सभी कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मनेंद्रगढ़, देतेवाड़ा, कुनकुरी और जाजगीर-चापा में निर्माणधीन मेडिकल कॉलेजों का कार्य अंतिम चरण में है, सरकार का उद्देश्य इसी शैक्षणिक सत्र से इन कॉलेजों में पढ़ाई प्रारंभ करना है, इसी उद्देश्य से एनएमसी के समझ आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उन्होंने दावा किया कि मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित लगभग 99 प्रतिशत मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन किया जा चुका

नया मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं कर सकी, जबकि वर्तमान सरकार एक साथ पांच मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की दिशा में काम कर रही है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपनी उपलब्धियों पर भी नजर डालनी चाहिए, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, दवाओं में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को भी स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, मंत्री ने दोहराया कि एनएमसी की आपत्तियाँ प्रक्रिया का हिस्सा हैं और सरकार उनका समाधान कर जल्द ही सभी पांचों मेडिकल कॉलेजों को शुरू कराने के लिए आश्वस्त है, उन्होंने कहा मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, हम मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं और मेडिकल कॉलेज शुरू होकर रहेंगे।

## चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को रायपुर तक बढ़ाने की मांग

### रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हफीज मेमन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र...

एमसीबी और कोयलांचल क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और छात्रों के हित में उठी आवाज, बेहतर स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी बेहद जरूरी...

—संवाददाता—  
मनेंद्रगढ़, 14 जून 2026 (घटती-घटना)।



### ट्रेन विस्तार के मुख्य आधार और क्षेत्र की जरूरतें

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिला सहित पूरे कोयलांचल क्षेत्र के नागरिकों की वर्षों पुरानी और बेहद महत्वपूर्ण मांग को लेकर युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हफीज मेमन ने देश के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव को एक औपचारिक पत्र लिखकर चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या- 18258) का विस्तार प्रदेश की राजधानी रायपुर तक करने का पुरजोर आग्रह किया है, इस ऐतिहासिक फैसले से क्षेत्र के विकास, व्यापार और आमजन को एक नई संजीवनी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

### पर्याप्त समय और टैक का सही उपयोग संभव

रेल मंत्री को भेजे गए पत्र में मजबूत तर्क दिया गया है कि वर्तमान में चिरमिरी से बिलासपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ी (संख्या -18258) रात को चिरमिरी से रवाना होकर सुबह लगभग 4:30 से 5:00 बजे के बीच बिलासपुर स्टेशन पहुंच जाती है, चूंकि यह गाड़ी सुबह बेहद जल्दी बिलासपुर पहुंच जाती है, इसलिए इस ट्रेन के रैक के पास आगे रायपुर तक जाने और वहां से वापस आने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहता है। बिना किसी अतिरिक्त संसाधन या रेल के पहियों को रोके, इस ट्रेन का विस्तार रायपुर तक आसानी से किया जा सकता है।

व्यापार और व्यवसाय की गति, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और आसपास का पूरा कोयलांचल क्षेत्र एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है, यहां के व्यापारियों को अपने कारोबार के सिलसिले में लगातार राजधानी रायपुर आना-जाना पड़ता है, सीधी ट्रेन होने से उनका व्यापार सुगम होगा, उच्च शिक्षा के लिए वरदान-क्षेत्र के सैकड़ों छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और बड़ी कौचिंग के लिए रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से बेहद असुविधाजनक परिस्थितियों में आवागमन करना पड़ता है।

### बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच...

एमसीबी और कोयलांचल क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा

सुविधाओं का भारी अभाव है, गंभीर मरीजों को आपातकालीन और बेहतर इलाज के लिए रायपुर के एम्स व अन्य बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, सीधी कनेक्टिविटी न होने से मरीजों की जान पर बन आती है।

### दोहरी ट्रेनों और बसों के झंझट से मिलेगी मुक्ति

वर्तमान में सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी न होने के कारण यहां के नागरिकों, छात्रों, बुजुर्गों और विशेषकर गंभीर मरीजों को बिलासपुर में उतरकर दूसरी ट्रेन या बसों का सहारा लेना पड़ता है, इस पूरी प्रक्रिया में न केवल उनका कीमती समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि उन्हें भारी मानसिक व शारीरिक परेशानी की सामना करना पड़ता है, आधी रात और सुबह के समय स्टेशन बदलने में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ती है।

### जनहित में त्वरित कार्रवाई की आस...

युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हफीज मेमन ने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से रेल मंत्री से करबद्ध प्रार्थना की है कि जनहित, छात्रहित और व्यापारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस चिरमिरी-बिलासपुर गाड़ी संख्या 18258 को रायपुर रेलवे स्टेशन तक विस्तारित करने की कृपा करें, क्षेत्र की जनता ने इस निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार और त्वरित कार्रवाई की आशा व्यक्त की है, जिसके लिए वे सदैव रेल मंत्रालय के आभारी रहेंगे।

# कोरिया जिले में साहू समाज का नेतृत्व कौन करेगा?



## छह महीने से अटकी चुनावी गाड़ी, अब नए पर्यवेक्षकों पर टिकी निगाहें...

**रवि सिंह-**  
कोरिया, 14 जून 2026 (घटती-घटना)। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह मानी जाती है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन कोरिया जिला साहू समाज में पिछले छह महीनों से चल रही चुनावी कवायद ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है क्या यहाँ अध्यक्ष जनता चुनेगी, सदस्य चुनेंगे, या फिर विवाद ही अध्यक्ष बनकर बैठ जाएगा? कोरिया जिले में साहू समाज का जिला अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल आज समाज के हर चौपाल, हर बैठक और हर द्वाड़सप ग्रुप में गूँज रहा है, वजह भी साफ है, पिछले छह महीनों में चुनाव की घोषणा हुई, स्थगित हुई, मतदाता सूची पर विवाद हुआ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बदले गए, इस्तीफे हुए, आरोप लगे, जवाब आए, खबरें छर्यीं, प्रदेश नेतृत्व सक्रिय हुआ और अब एक बार फिर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन अध्यक्ष का नाम आज भी फाइलों, बैठकों और चर्चाओं के बीच कहीं अटका हुआ है। **25 हजार की आबादी और**

**लोकतंत्र का '73 मॉडल'**  
पूरे विवाद की जड़ वही संख्या है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान कोरिया की ओर खींचा था—73 मतदाता, समाज के जानकारों के अनुसार कोरिया जिले में साहू समाज की आबादी लगभग 25 हजार से अधिक मानी जाती है, जिले के अनेक गांवों, कस्बों और शहरों में समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, ऐसे में जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और मतदाता सूची सामने आई तो उसमें मात्र 73 नाम दिखाई दिए, बस यहीं से सवाल की बाढ़ आ गई, लोग पूछने लगे कि क्या 25 हजार लोगों के सामाजिक भविष्य का फैसला सिर्फ 73 लोग करेंगे? क्या बाकी समाज केवल दर्शक बना रहेगा? क्या संगठन की सदस्यता इतनी सीमित हो चुकी है या फिर सदस्यता विस्तार का प्रयास ही नहीं किया गया? व्यंग्य करने वाले तो यहाँ तक कहने लगे कि यदि यही लोकतंत्र का नया मॉडल है तो भविष्य में पंचायत चुनाव भी दो मोहल्लों और विधानसभा चुनाव चार गलियों से करा लिए जाएं।

**25 हजार की आबादी, लेकिन मतदाता सिर्फ 73! अध्यक्ष चुनाव से पहले फिर खड़े हुए बड़े सवाल...**  
**73 बनाम 25 हजार का महासंग्राम : आखिर कोरिया साहू समाज का अध्यक्ष कौन बनेगा?**  
**छह महीने से कुर्सी खाली, बैठकों का अंबार, पत्रों की भरमार, पर्यवेक्षक फिर तैयार; समाज पूछ रहा है चुनाव होगा या फिर नया इंतजार?**  
**कोरिया साहू समाज में फिर चुनावी शंखनाद, सवाल वही—मतदाता बढ़ेंगे या विवाद?**

**पत्र, बैठक, विवाद और पर्यवेक्षक, फिर भी नहीं तय हो पाया साहू समाज का नया सरदार...**  
**साहू समाज का चुनाव या सीमित लोकतंत्र का प्रयोग? 25 हजार लोगों के बीच 73 मतदाताओं पर बहस तेज**  
**कुर्सी खाली, दावेदार तैयार, समाज इंतजार में, क्या इस बार निष्पक्ष होगा साहू समाज का चुनाव?**  
**25 हजार का समाज, 73 का लोकतंत्र! अब पर्यवेक्षक बताएंगे अध्यक्ष का रास्ता**

**खबरों ने हिलाई व्यवस्था, प्रदेश नेतृत्व को करना पड़ा हस्तक्षेप...**  
जनवरी और फरवरी के दौरान लगातार प्रकाशित खबरों ने इस पूरे मामले को समाज के भीतर से निकालकर सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया, मतदाता सूची, सदस्यता, चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल लगातार बढ़ते गए, समाज के अनेक वरिष्ठ और युवा सदस्यों ने खुलकर कहा कि चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलाया जाना चाहिए, जब विवाद बढ़ा तो चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगी, चुनाव स्थगित हुआ, फिर नई चर्चाएं शुरू हुईं। फिर नई बैठकों का दौर चला, अब हालात ऐसे बने कि प्रदेश साहू संघ को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा और आखिरकार 13 जून 2026 को संशोधित आदेश जारी कर कोरिया जिले के लिए नए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए।  
**पर्यवेक्षक आए हैं, लेकिन क्या व्यवस्था भी बदलेगी?**  
प्रदेश साहू संघ ने रायपुर के सत्यप्रकाश साहू और प्रदीप साहू को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कराई जाएगी तथा सदस्यता, मतदाता सूची, आय-व्यय, दस्तावेज और अन्य अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी, लेकिन समाज के भीतर अब चर्चा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से आगे बढ़ चुकी है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या पर्यवेक्षक केवल चुनाव करवाने आए हैं या चुनाव से पहले उन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे जिनकी वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ था? क्योंकि यदि पुरानी सूची के आधार पर चुनाव करा दिया गया तो फिर वही सवाल उठेंगे जो पिछले छह महीनों से उठ रहे हैं।  
**समाज चाहता है पहले सदस्य बढ़ें, फिर अध्यक्ष चुना जाए...**  
समाज के एक बड़े वर्ग की मांग है कि चुनाव से पहले व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाए, उनका तर्क सीधा है, जब समाज की आबादी हजारों में है तो मतदाता सूची भी व्यापक होनी चाहिए, गांव-गांव जाकर सदस्य बनाए जाएं, युवाओं को जोड़ा जाए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, इसके बाद नई मतदाता सूची प्रकाशित की जाए और फिर चुनाव कराया जाए, कई समाजजन मानते हैं कि अध्यक्ष पद की असली ताकत वोटों की संख्या में नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता में होती है, यदि चुनाव सीमित दायरे में होगा तो परिणाम चाहे जो हो, विवाद खत्म नहीं होगा।  
**कुर्सी की लड़ाई या समाज का नेतृत्व?**  
पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने एक ओर बहस को जन्म दिया है, क्या चुनाव वास्तव में समाज के विकास के लिए हो रहा है या फिर यह केवल अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने की होड़ बनकर रह गया है? कई वरिष्ठ समाजजन कहते हैं कि संगठन का उद्देश्य सामाजिक एकता, शिक्षा, आर्थिक उन्नति और सामुदायिक विकास होना चाहिए, लेकिन पिछले महीनों में चर्चा विकास की कम और अध्यक्ष पद की ज्यादा दिखाई दी, कुर्सी अभी तक खाली है, लेकिन उसके आसपास राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।  
**अब फैसला पर्यवेक्षकों के हाथ में नहीं, भरोसे के हाथ में है...**  
सत्यप्रकाश साहू और प्रदीप साहू की नियुक्ति के बाद चुनावी प्रक्रिया एक बार फिर पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है, लेकिन असली चुनौती चुनाव करना नहीं है, बल्कि चुनाव पर समाज का भरोसा वापस लाना है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव एक दिन में हो जाएगा, मतगणना भी कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी, परिणाम भी घोषित हो जाएगा, लेकिन यदि समाज का विश्वास नहीं जीता गया तो विवाद का चुनाव खत्म होगा, विवाद नहीं, कोरिया का साहू समाज आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसे सिर्फ अध्यक्ष नहीं चुनना है, बल्कि यह तय करना है कि आने वाले वर्षों में उसका संगठन सीमित दायरे का क्लब बनेगा या फिर 25 हजार लोगों की सामूहिक आवाज, और फिलहाल यही सवाल पूरे जिले में गूँज रहा है अध्यक्ष कौन बनेगा? से भी बड़ा सवाल है अध्यक्ष को चुनने का अधिकार आखिर किन-किन लोगों को मिलेगा?

**कोरिया का चुनाव, पूरे प्रदेश की नजर...**  
अब यह केवल कोरिया जिले का मामला नहीं रह गया है, जिस तरह यह विवाद लगातार चर्चा में रहा, उससे प्रदेश स्तर पर भी लोगों की नजर इस चुनाव पर टिक गई है, कई जिलों के समाजजन यह देखना चाहते हैं कि प्रदेश नेतृत्व आखिर इस मामले को किस तरह सुलझाता है, क्या सदस्यता का विस्तार होगा? क्या नई मतदाता सूची बनेगी? क्या पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या सभी पक्षों को साथ लेकर चुनाव होगा? या फिर केवल तारीख बदलेगी और पुरानी कहानी नए कागज पर लिख दी जाएगी?  
**सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है...**  
इन तमाम बैठकों, आदेशों, नियुक्तियों और चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है क्या इस बार अध्यक्ष निष्पक्ष तरीके से चुना जाएगा? क्या समाज के अधिक लोगों को मतदान का अधिकार मिलेगा? क्या 73 की संख्या बढ़कर सैकड़ों या हजारों तक पहुंचेगी? क्या समाज की नई पीढ़ी को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण— क्या चुनाव जाने वाला अध्यक्ष पूरे 25 हजार लोगों का प्रतिनिधि होगा या फिर केवल मतदाता सूची में दर्ज कुछ नामों का?

क्र.	जिला का नाम	पर्यवेक्षक का नाम	पता	मो. नं.
1.	मिलरपुर	जी. सुनील साहू, श्रीमती. मीना साहू	दुर्ग बस्ती, गुरु	9300646659 / 786889801
2.	कोरिया	जी. सत्यप्रकाश साहू, श्री प्रदीप साहू	रायपुर	8892541542 / 8871234066
3.	पारसगढ़	जी. मिलर साहू, श्रीमती. सारंग साहू	मिलरपुर, रायपुर	8839944578 / 9131020065

# 7 रुपये की मजदूरी और करोड़ों के दावे, आखिर मनरेगा में मजदूरों का पैसा गया कहाँ?

## भरतपुर के नौडिया में मजदूरी भुगतान पर बड़ा सवाल, पसीना मजदूरों का और भुगतान मजाक जैसा!



विकास क्षेत्र	ग्राम	मजदूर	दिनांक	मजदूरी	व्यय	विवरण	प्रकार	व्यय कोड	व्यय विवरण
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सरकार को घेरा...**  
मामला सामने आने के बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है, उन्होंने इसे गरीब मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि यदि मजदूरों को उनका पूरा भुगतान नहीं मिला है तो यह बेहद गंभीर मामला है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा, उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।  
**सवाल जो जवाब मांग रहे हैं...**  
इस पूरे मामले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं, यदि मस्टर रोल में पूरी मजदूरी दर्ज है तो भुगतान कम क्यों हुआ? क्या यह तकनीकी त्रुटि है या फिर भुगतान प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी? क्या मजदूरों के खातों तक राशि पहुंचने से पहले कहीं कटौती हुई? क्या पंचायत, जनपद या संबंधित विभागों ने भुगतान की जांच की? और सबसे बड़ा सवाल—यदि वास्तव में मजदूरों को सात रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिला है तो बाकी राशि कहाँ गई?  
**व्यवस्था पर व्यंग्य भी कम नहीं...**  
ग्रामीणों के बीच इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं, लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में जहाँ सात रुपये में एक कप चाय भी मुश्किल से मिलती है, वहाँ सरकार के रिकॉर्ड में शायद मजदूरों का पूरा दिन सात रुपये में गुजर जाता होगा, किसी ने कहा कि यदि यही मजदूरी का नया मॉडल है तो आने वाले दिनों में शायद मजदूरों को मजदूरी के साथ धन्यवाद पत्र भी दिया जाए, वहीं कुछ लोग इसे गरीबों के साथ करुण मजाक बता रहे हैं।  
**जांच से ही सामने आएगा सच...**  
हालांकि पूरे मामले की वास्तविकता प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, यह भी संभव है कि भुगतान प्रक्रिया में कोई तकनीकी त्रुटि या अधूरी एंट्री हुई हो, लेकिन जब तक संबंधित विभाग स्थिति स्पष्ट नहीं करता, तब तक मजदूरों की नाराजगी और सवाल दोनों बने रहेंगे, फिलहाल नौडिया गांव में सबसे बड़ा सवाल यही गूँज रहा है मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी सात रुपये कैसे हो गई, और यदि नहीं हुई तो फिर खातों में इतनी कम राशि क्यों पहुंची? अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला केवल 100 मजदूरों का नहीं, बल्कि उन सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता का भी है जिनके सहारे ग्रामीण गरीब अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं।

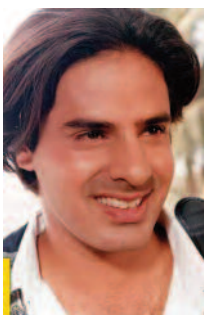
**मजदूरों के हक पर डाका, भाजपा सरकार जवाब दे!**  
— गुलाब कमरो  
—संवाददाता—  
एमसीबी/भरतपुर, 14 जून 2026 (घटती-घटना)। सरकारें चाहे जितने दावे कर लें कि गरीबों के उत्थान और मजदूरों के सम्मान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन भरतपुर विकासखंड के ग्राम नौडिया से सामने आई खबर ने इन दावों की चमक पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है, यहाँ मनरेगा और पंचायत कार्यों में लगे करीब 100 मजदूरों को

कथित तौर पर मजदूरी के नाम पर प्रतिदिन महज 7 रुपये का भुगतान मिलने की बात सामने आई है, इस खुलासे के बाद मजदूरों में आक्रोश है और प्रशासन की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो गई है, जिस मनरेगा योजना को ग्रामीण गरीबों की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार माना जाता है, उसी योजना में यदि दिनभर कड़ी धूप में काम करने वाले मजदूरों को सात रुपये प्रतिदिन का भुगतान मिलने तो यह केवल त्रुटि नहीं बल्कि व्यवस्था पर गंभीर सवाल है।  
**पसीना बहाया मजदूरों ने, रकम देखकर उड़ गए होश...**  
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नौडिया में विभिन्न पंचायत और मनरेगा कार्यों में लगे मजदूरों ने जब अपने खातों की जांच की तो वे हैरान रह गए, जिन मजदूरों को तय मजदूरी मिलने की उम्मीद थी, उनके खाते में बेहद कम राशि जमा हुई, कई मजदूरों का आरोप है कि

भुगतान की गणना के आधार पर उन्हें प्रतिदिन लगभग 7 रुपये के बराबर राशि प्राप्त हुई, गांव में चर्चा का विषय यही है कि आखिर मजदूरों की मेहनत का मूल्य इतना कम कैसे हो सकता है, जिन हाथों ने मिट्टी काटी, तालाब खोदे, सड़क बनाई और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारा, उन्हीं हाथों में मजदूरी के नाम पर इतनी छोटी राशि पहुंचना लोगों को समझ से परे लग रहा है।

## एक दिन में 47 फिल्मों पर साइनिंग, फिल्म इंडस्ट्री में मचा था हड़कंप

बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता राहुल रॉय एक बार फिर चर्चा में हैं। 'आशिकी' फिल्म से रातोंरात स्टार बने राहुल रॉय ने अपने करियर के शुरुआती दौर में ऐसी लोकप्रियता हासिल की थी कि उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। हाल ही में एक टीवी शो के दौरान उन्होंने अपने



फिल्मी करियर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक समय में एक दिन में 47 फिल्मों साइन कर ली थीं। इस बात ने सभी को हैरान कर दिया। राहुल रॉय ने बताया कि सोशल मीडिया और शो में फैल रही यह बात कि उन्होंने एक दिन में 150 फिल्मों साइन की थीं, पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी 150 फिल्मों साइन नहीं कीं, बल्कि उनके पास एक समय में 47 फिल्मों के ऑफर आए थे, जिन पर उन्होंने साइन किया था। इस खुलासे के बाद वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। राहुल रॉय को 'आशिकी बॉय' के नाम से पहचान मिली थी, क्योंकि उनकी पहली फिल्म 'आशिकी' सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री अनु अग्रवाल नजर आई थीं। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है और बताया जाता है कि यह लंबे समय तक सिनेमाघरों में हाउसफुल रही थी। इस फिल्म की सफलता ने राहुल रॉय को अचानक स्टार बना दिया था। सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स साइन कर लिए, लेकिन बाद में उन्होंने खुद बताया कि उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का समय नहीं था। इसी वजह से उन्हें कई प्रोड्यूसर्स को पैसे वापस करने पड़े थे। करीब 21 प्रोड्यूसर्स को भुगतान लौटाना पड़ा था क्योंकि वे सभी फिल्मों में काम नहीं कर सके। राहुल रॉय ने अपने करियर में 28 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन समय के साथ उनका स्टारडम पहले जैसा नहीं रहा। उनकी कई फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकीं। इसके बाद वे धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले गए। हालांकि उन्होंने रियलिटी शो 'बिग बॉस' के पहले सीजन में हिस्सा लिया और इसके विजेता भी बने, जिससे उन्हें फिर से पहचान मिली।

हाल ही में राहुल रॉय सोशल मीडिया पर एक इंफ्लुएंसर के साथ रील बनाने को लेकर ट्रोल् भी हुए थे। कुछ लोगों ने इसे उनके करियर का डाउनफॉल बताया, जबकि कुछ ने सवाल उठाए कि उन्हें ऐसी रील बनाने की क्या जरूरत है। इन ट्रोल्स पर जवाब देते हुए राहुल रॉय ने कहा था कि वे अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और उन्हें अपने खर्च और कानूनी मामलों को संभालने के लिए काम करना पड़ता है, जो उनके ब्रेन स्ट्रोक से पहले के समय से जुड़े हुए हैं।

## वेलकम टू द जंगल ने रिलीज से पहले रचा इतिहास

कैसे 2026 की नंबर 1 फिल्म बनी अक्षय कुमार की ऐक्शन कमेडी? हाल ही में मुंबई में एक शानदार इवेंट में वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर रिलीज किया गया, जहां जंगल-थीम वाली सजावट की गई थी। इस इवेंट में जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, जानी लीवर, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार समेत कई बड़े स्टार्स शामिल हुए।

**ट्रेलर को मिला जबरदस्त रियांस**  
ट्रेलर को तो जबरदस्त रियांस मिला ही है लेकिन वेलकम टू द जंगल ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। ट्रेलर को दो दिनों में ही यूट्यूब पर 28 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, यह फिल्म एक और लिस्ट में भी आधिकारिक तौर पर नंबर 1 पर है।

### वेलकम टू द जंगल ने रचा इतिहास

अहमद खान की डायरेक्ट की हुई फिल्म वेलकम टू द जंगल अभी आईएमडीबी पर सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही टॉप 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह इस बात का सबूत है कि दर्शकों में इसे लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। आखिरकार, डब्ल्यूटीडीजे में अक्षय का वही पुराना अंदाज (ओजी अक्षय) वापस आ रहा है, जो 2007



की कल्ट क्लासिक फिल्म वेलकम टू द जंगल का रचा है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी, गलत पहचान के इर्द-गिर्द घूमती है। एक स्टारलिंग एक्टर (अक्षय का किरदार) जंगल में एक ऐक्शन फिल्म की

शूटिंग कर रहा है। बात आगे बढ़ती है और वहां के लोग फिल्म की कू को असली आर्मी वाले समझ बैठते हैं, जो उन्हें मुसीबत से बचाने आए हैं। फिल्म में करीब 40 कलाकार नजर आने वाले हैं जो अब तक की सबसे बड़ी कार्टिंग मानी जा रही है।

### अक्षय का वर्कफ्रंट

अक्षय हाल ही में प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई 'हॉर-कॉमेडी' फिल्म भूत बंगला की सफलता के बाद साथ आ रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इसके बाद उनकी अपकॉमिंग फिल्मों में हैवान और गोलमाल 5 भी हैं।

## विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शादी के बाद लिया बड़ा फैसला



जरूरतमंद छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और शिक्षा के स्तर को सुधारना है। दोनों कलाकारों का मानना है कि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसी के माध्यम से भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इस पहल के तहत स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, छात्रों को प्रोत्साहित करने और शिक्षा से जुड़ी बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी इस प्रयास को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एक बार फिर चर्चा में हैं। दोनों ने अब एक सामाजिक पहल के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। यह कदम तेलंगाना में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और समय-समय पर अलग-अलग क्षेत्रों में मदद करते आए हैं। अब दोनों ने मिलकर तेलंगाना में शिक्षा की बेहतरी के लिए किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस पहल का उद्देश्य

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के इस कदम को उनके फैंस और सामाजिक संगठनों द्वारा सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि फिल्मी सितारों का इस तरह समाज के लिए आगे आना प्रेरणादायक है और इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। दोनों कलाकारों ने पहले भी कई बार जरूरतमंदों की मदद की है, लेकिन इस बार उनकी यह पहल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। इस तरह विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का यह प्रयास न केवल तेलंगाना के छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बल्कि यह समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

## छोटी ड्रेस पहनने के लिए डायरेक्टर ने भाग्यश्री डाला था दबाव

37 साल बाद सलमान की हीरोइन ने किया खुलासा

सलमान खान की पहली लीड हीरोइन भाग्यश्री को भला कौन नहीं जानता। 90 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी और बेबाक खूबसूरती के दम पर फैंस के दिलों पर राज करने वाली भाग्यश्री ने हाल ही में एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। भाग्यश्री ने बताया है एक फिल्म में शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए डायरेक्टर ने उन्हें बार-बार फोर्स किया था, लेकिन एक्ट्रेस ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं-



**भाग्यश्री ने किया था इनकार**  
कई बार इनकार करना भी, सीन को बेहतर बना सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मैंने प्यार किया फिल्म के गाने मेरे रंग में रंगने वाली गाने के दौरान भी। उस गाने में प्रेमिका का बर्थडे मना रहे सलमान खान का पात्र प्रेम अपनी प्रेमिका सुमन के लिए कई ड्रेस लेकर आता है, जिसमें से एक छोटी ड्रेस भी होती है। उस ड्रेस को पहनने से सुमन का रोल निभाने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री ने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने पूरा सीन ही बदल दिया था। भाग्यश्री उस फिल्म को याद करते हुए वैराइटी शो इंडिया को इंटरव्यू देते हुए अभिनेत्री ने कहा है...सूरज जी ने कहा कि पूरी फिल्म तुम्हारे अनुसार बनने वाली है, बस एक ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि ये ड्रेस पहने का मतलब होगा कि वह अपने प्रेमी पर भरोसा कर रही है। मैंने कहा, मैं नहीं पहनूंगी। फिर सूरज जी ने मुझे हेमा (मालिनी) जी का क्रांति फिल्म का गाना जिंदगी की ना टूटे लड़की...दिखाया और कहा कि हेमा जी ने स्कर्ट पहनी है, जो उनके घुटनों तक है। उन्होंने पहना, तो तुम नहीं पहन सकती हो। मैंने कहा...नहीं। आज लगता है कि एक छोटे से बदलाव ने सीन को कितना यादगार बना दिया है। मैंने कहा कि अगर वह प्रेमी पर भरोसा करती है तो वह ड्रेस केवल उसे दिखाएगी, दुनिया को नहीं। सूरज जी ने कहा, हां इस सीन का मतलब बनता है। आज के दौर में भी बतौर लीड एक्ट्रेस भाग्यश्री सिनेमा जगत में एक्टिव हैं। इस दौरान वह हिंदी, साउथ और मराठी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी का जलवा बिखेर रही हैं। हाल ही में उन्हें अभिनेता तिरेश देशमुख की मराठी फिल्म राजा शिवाजी में देखा गया है, जिसमें भाग्यश्री ने महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजाबाई की अहम भूमिका को अदा किया है।

## 10 सिंगर्स के रिजेक्शन के बाद बनी अनु मलिक की आवाज में कल्ट हिट

बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अनु मलिक का नाम एक ऐसे संगीतकार के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने न सिर्फ कई यादगार गाने दिए, बल्कि कई सिंगर्स के करियर को भी नई दिशा दी। वह केवल एक गायक ही नहीं, बल्कि एक म्यूजिक कंपोजर और स्कोर कंपोजर के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान रखते हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को कई सुपरहिट गानों से समृद्ध किया है। अनु मलिक की खासियत यह मानी जाती है कि वह किसी भी गाने की रचना करते समय ही यह समझ लेते थे कि उस गाने के लिए किस तरह की आवाज सबसे उपयुक्त रहेगी। इसी कारण उनके बनाए गए कई गाने समय के साथ लोकप्रिय होते चले गए और आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में कई नए और उभरते हुए सिंगर्स को मौका दिया, जिन्होंने आगे चलकर म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। कई कलाकारों के लिए अनु मलिक का संगीत एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। माना जाता है कि अनु मलिक का संगीत बनाने का तरीका काफी अलग और रचनात्मक रहा है। वह धुन तैयार करते समय हर बारीकी पर ध्यान देते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि गीत की भावनाएं, शब्द और आवाज एक साथ मिलकर



प्रभावशाली अनुभव दें। इसी कारण उनके कई गाने लंबे समय तक लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे। बॉलीवुड में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में अनु मलिक का संगीत काफी छाया रहा। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के प्रमुख संगीतकारों की सूची में शामिल कर दिया। उनके गानों में रोमांस, दर्द, उत्साह और मनोरंजन का अनेकाने मिश्रण देखने को मिलता है।

## खेल समाचार

# भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया

दीप्ति ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए; स्मृति मंधाना ने 68 रन बनाए

बर्मिंघम, 14 जून 2026। भारत ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। एजबेस्टन में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 17 बॉल पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। तस्मिया रुबाब और रमीन शमीम को 1-1 सफलता मिली। 171 रन का पीछ कर रही पाकिस्तान 17 ओवर में 106 रन पर ऑलआउट हो गईं। मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए। श्री चर्णी



को 3 और शेफाली वर्मा को एक विकेट मिला। दोनों टीमों की प्लेइंग-11  
भारत : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चर्णी, क्रांति गौड़।  
पाकिस्तान : मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, आलिया रियाज, सायरा जबीन, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल।



## पुर्तगाल वर्ल्ड कप में दिवंगत डियोगो जोटा को यादगार रिस्टबैंड के साथ सम्मानित करेगा

मियामी, 14 जून 2026। अगले हफ्ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के खिलाफ अपने ग्रुप के पहले मैच से पहले, मिडफील्डर विटिनहा ने कहा कि पुर्तगाल अपनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुहिम के दौरान खास यादगार रिस्टबैंड पहनकर पूर्व फोरवर्ड डियोगो जोटा को श्रद्धांजलि देगा। रॉयटर्स के अनुसार, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने टीम को ये रिस्टबैंड दिए थे। इन पर सभी मौजूदा खिलाड़ियों के साथ-साथ जोटा का नाम भी लिखा है, जिनकी पिछले साल उत्तर-पश्चिमी स्पेन में एक कार दुर्घटना में अपने भाई के साथ मौत हो गई थी। जोटा, जिन्होंने पुर्तगाल के लिए 49 मैच खेले और 14 गोल किए, राष्ट्रीय टीम में एक बहुत पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उनके साथियों ने टूर्नामेंट के दौरान मैदान पर उनकी यादों को साथ ले जाने का फ़ैसला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक, विटिनहा ने पत्रकारों से कहा, असल में, रिस्टबैंड की कहानी यह है कि जब हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो उन्होंने हमें यह रिस्टबैंड दिया। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने यह पक्का किया कि यह ऐसा रिस्टबैंड है जो जिसे हम मैदान पर पहन सकें। इसमें वे सभी खुशियां हैं जिनकी वजह से हम इस पसंद मैदान पर उतर सकते हैं; इसमें सभी खिलाड़ियों के नामों के साथ-साथ डियोगो

जोटा का खास नाम भी शामिल है। विटिनहा ने आगे कहा, उन्होंने हमें यह चुनने की आजादी दी कि हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, और कैसे (दिन के समय या मैच के दौरान)। हमने इसे बहुत प्यार से स्वीकार किया और इसका इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। पुर्तगाल बुधवार को अपनी वर्ल्ड कप मुहिम शुरू करेगा और हाल के वर्षों में शानदार फॉर्म के बाद टूर्नामेंट में बड़ी उम्मीदों के साथ उतरेगा। हालांकि, विटिनहा ने जोर देकर कहा कि टीम में बहुत टैलेंट होने के बावजूद वे सावधानी के साथ इस प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं। पेरिस सेंट-जर्मेन के मिडफील्डर, जिन्होंने पेरेंस क्लब के साथ लगातार फीफा चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं, ने कहा कि अगर पुर्तगाल को चार साल पहले कतर में छाट्टर फ़ाइनल से बाहर होने के बाद टूर्नामेंट में आगे तक जाना है, तो विनग्रता बहुत जरूरी होगी। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि हम फेवरेट हैं, लेकिन हमारे पास टूर्नामेंट में आगे तक जाने की बेहतरीन क्वालिटी और क्षमता है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि सही रास्ता विनग्र बने रहना और सही खेल खेलना है। हमारे पास टैलेंट है, बस हमें टेक्निकल और टैटिकल पहलुओं (को एक साथ लाने) की जरूरत है।



## मानव कृष्णा का यू-19 टीम में चयन

तिरुवनंतपुरम, 14 जून 2026। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टेस्ट टीम में केरल के अंडर-19 कप्तान और होनहार विकेटकीपर-बल्लेबाज मानव कृष्णा को चुना गया है। भारत श्रीलंका में तीन वनडे और दो चार-दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगा। पेरुक्कडा के रहने वाले मानव को घरेलू सीजन में जबरदस्त बल्लेबाजी और विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। कृष्णा ने पिछले अंडर-19 सीजन में 592 रन बनाए और कूच बिहार ट्रॉफी में लगातार शतक लगाए, जिसमें सौराष्ट्र के खिलाफ 189 रन और हैदराबाद के खिलाफ 144 रन की पारी शामिल है। मानव ने दिल्ली में अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की और 12 साल की उम्र में केरल चले गए। बाद में वे केरल की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के कप्तान बने और अपनी लीडरशिप और एथलेटिक काबिलियत के

लिए पहचान बनाई। श्रीलंका सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टेस्ट टीम में चुने जाने पर कृष्णा ने कहा, मैं एक राइट-हैंड बल्लेबाज और विकेटकीपर-बल्लेबाज हूँ, और अंडर-19 टीम में चुने जाने पर बहुत खुश हूँ। भारत के लिए खेलना हमेशा से मेरा सपना और लक्ष्य रहा है... मैं कॉन्फिडेंट हूँ और साथ ही नर्वस और उत्साहित भी। मैंने दिल्ली में अपना करियर शुरू किया, फिर 12 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। कृष्णा ने पिछले अंडर-19 सीजन में 592 रन बनाए और कूच बिहार ट्रॉफी में लगातार शतक लगाए, जिसमें सौराष्ट्र के खिलाफ 189 रन और हैदराबाद के खिलाफ 144 रन की पारी शामिल है। मानव ने दिल्ली में अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की और 12 साल की उम्र में केरल चले गए। बाद में वे केरल की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के कप्तान बने और अपनी लीडरशिप और एथलेटिक काबिलियत के

केरल की अंडर-19 टीम के सदस्य हैं। मानव उन्नीकृष्णन और अनीता के बेटे हैं। वे तिरुवनंतपुरम में अपने कोच स्टेन शान की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं। एज-रूप क्रिकेट से नेशनल टीम तक उनका पहुंचना केरल क्रिकेट के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है और इससे रॉयल से उभरने वाले युवा टैलेंट की लिस्ट और लंबी हो गई है। शाइन ने कहा, वह बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं। वह हर तरह के फॉर्म में खुद को ढाल सकते हैं। जब वह अंडर-16 टीम के लिए खेल रहे थे, तो पहले साल मैं उनका कोच था। उस समय उन्होंने लगभग दो शतक लगाए थे। उसके बाद, वह सीधे अंडर-19 टीम में गए और लगभग 600 रन बनाए। इसके बाद, उनका सिलेक्शन एनसीए (नेशनल क्रिकेट एकेडमी) में हुआ। उनकी विकेटकीपिंग की बात करें तो वह बहुत तेज विकेटकीपर हैं। वह स्वभाव से भी बहुत शांत हैं और मैदान पर आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाते हैं।

सीएम साय ने जांजगीर-चांपा जिले में 295 करोड़ रुपये से अधिक के 341 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

विकास कार्यों से आमजन की सुविधाओं का होगा विस्तार : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 14 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राख) में आयोजित कार्यक्रम में जिलेवासियों को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री साय ने 295 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 70.10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 159 कार्यों का लोकार्पण तथा 224.90 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 182 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इन विकास कार्यों के माध्यम से सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय अधोसंरचना तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा और जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधिविधान से पूजा-अर्चना कर विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया तथा बटन दबाकर पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन जांजगीर-चांपा जिले के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले को लगभग 295 करोड़



रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है, जिससे क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और जनजीवन अधिक सुगम



सिंचाई, स्वास्थ्य और अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन

संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सीजीएमएससी, नगरीय प्रशासन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्य शामिल हैं। वहीं भूमिपूजन के 182 कार्यों में जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, सीजीएमएससी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, नगरीय प्रशासन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य केवल निर्माण नहीं होते, बल्कि वे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है और इसी सोच के साथ प्रदेश में विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

राहुल गांधी का 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा पक्का, मिशन 2028 की तैयारी शुरू?

न्यायधानी में सर्पदंश मुआवजा महाघोटाला : सामान्य मौत को सांप का काटा बताकर 60 लाख डकारे, 17 केस फर्जी, डॉक्टर-वकील पर एफआईआर तय

बिलासपुर, 14 जून 2026। रायपुर के कांग्रेस दफतर में इन दिनों खासी गहमागहमी है। पार्टी आलाकमान ने संगठन को जमीन पर उतारने का जो प्लान बनाया है, उसकी शुरुआत राजधानी से हो रही है। 21 जून से 30 जून तक चलने वाले इस 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैम्प में प्रदेश भर के दिग्गज जुटेंगे। लेकिन असली शोर तो 28 जून को मचेगा।

राहुल गांधी का दो दिन का दौरा

सूत्रों की मानें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 28 जून को रायपुर लैंड करेंगे। उनका ये दौरा सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि दो दिन का रहने वाला है। वे यहां के ट्रेनिंग कैम्प में शामिल होकर सीधे जिला और शहर अख्यक्षों से फीडबैक लेंगे। बुध लेवल पर पार्टी कैसे काम कर रही है, इसका पूरा हिसाब-किताब राहुल गांधी खुद लेंगे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के लेटर जारी करते ही रायपुर में तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। हर बुध पर कार्यक्रमों की सक्रियता जांची जाएगी। आगामी चुनावों को लेकर नेताओं की 'ग्राउंड लेवल' की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला और शहर अख्यक्षों के बीच बेहतर सामंजस्य बिठाने पर जोर होगा। राहुल गांधी का दौरा सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहने वाला। रायपुर की



सड़कों और चौक-चौराहों पर चर्चा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में आ रही है। आलाकमान की कोशिश है कि इस 10 दिवसीय कैम्प के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना तैयार कर दिया जाए कि वे हर राजनीतिक चुनौती का डटकर सामना कर सकें। क्या यह दौरा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? राहुल गांधी के इस दौर के बाद रायपुर से लेकर बस्तर तक की राजनीति में कितना असर दिखेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त जोश है।

बिलासपुर, 14 जून 2026। न्यायधानी बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। डॉक्टरों और वकीलों ने मिलकर जहर सेवन और सामान्य मौतों को सांप के काटने से हुई मौत दिखाकर सरकारी खजाने से करीब 60 लाख रुपये हड़प लिए। जांच में 17 मामले पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं। प्रशासन 15 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है।

केसे हुआ घोटाला?

दलालों के नेटवर्क ने डॉक्टर, पुलिस विवेचना अधिकारी और वकीलों से साटासाट कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। जहर खाकर आत्महत्या या सामान्य मौत को भी सर्पदंश में बदल दिया गया। फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल में फर्जी भर्ती के कागज बनाकर जिला प्रशासन से मुआवजा ले लिया गया।

विधायक ने खोली पील

बेलतरा विधायक सुरशांत शुक्ला ने विधानसभा में मामला उठाया था। इसके बाद सचिव स्तरीय जांच में संशुद्धि भ्रष्टाचार की



पत्रों खुलीं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी राहत राशि हड़पने के मामले में बिल्ला और सरकंडा थानों में पहले ही अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। अब जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही अन्य संबंधित थानों में भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। मजे की बात यह है कि नागलोक कहे जाने वाले जशपुर में सर्पदंश से सिर्फ 96 मौतें हुईं और 3 करोड़ मुआवजा बंटता। वहीं बिलासपुर में 431 मौतें दिखाकर 17

17 मामलों में फर्जीवाड़ा प्रमाणित

एसडीएम मनीष साहू ने बताया कि 17 मामलों में फर्जीवाड़ा प्रमाणित हो चुका है। सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टरों, वकीलों और अन्य आरोपियों पर एफआईआर होगी।

फर्जी पाए गए ये सभी मामले

बिलासपुर जिले में अब तक हुई जांच में जिनकी मौतों को फर्जी तरीके से सर्पदंश से मौत का बता दिया गया था उनमें शिवकुमारी यादव तालापारा, सुनिता बाई सोनवानी तखतपुर, संतोष कुमार महमद, कुती बाई प्रजापति तालापारा, केशव कुमार कश्यप, सफीना बानो महमद, भागत सिंह ठाकुर कोनी, बहोरन लाल जायसवाल खमतराई, शंकर साहू सरकंडा, अशोक कुमार खमतराई, राशि पाठक सरकंडा, राजू कुमार सरकंडा, निर्मला धुलढारे, मनसुख लाल साहू, रामनारायण केवत कोनी, लक्ष्मीन कुर्न चोरी, उर्वशी श्रीवास्तव तखतपुर की मौत से जुड़ा मामला शामिल है।

नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हदसा तेज रफतार ट्रेलर की टक्कर से बाइक जलकर खाक, युवक की मौके पर मौत



ट्रेलर की टक्कर के बाद आग का गोला बनी बाइक युवक की दर्दनाक मौत

दुर्ग, 14 जून 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफतार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक की पेट्रोल टंकी फट गई और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग-राजनांदगांव बाईपास मार्ग की है। जानकारी के अनुसार, युवक बाइक क्रमांक CG 07 CV 3947 पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर क्रमांक JH 05 DS 0514 ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक की पेट्रोल टंकी फट गई, जिससे उसमें आग लग गई। इसके बाद कुछ ही मिनटों में बाइक जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बाइक पर अकेला सवार था। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद मोहन नगर थाना पुलिस और एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया है।

हाईकोर्ट का सत्र वेकेशन खत्म... आज से नियमित सुनवाई, ईंधन बचाने अधिकारी-कर्मचारियों को वाहन शेयर करने की सलाह, वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त

बिलासपुर, 14 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। सोमवार 15 जून से हाईकोर्ट की सभी निर्धारित बेंचों में नियमित सुनवाई शुरू होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईंधन की बचत करने और सरकारी वाहनों का साझा उपयोग करने की सलाह दी है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना अभी भी जरूरी है। न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर ही सरकारी वाहनों का उपयोग करें। हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां संभव हो, वे अपने सरकारी वाहनों का उपयोग नया अधिकारियों के साथ साझा करें। इससे ईंधन की बचत होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। हाईकोर्ट में 18 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हुआ था। इस दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंचों का गठन किया गया था। प्रत्येक सप्ताह डिजीवन बेंच और सिंगल बेंच में निर्धारित दिनों पर सुनवाई जारी रही। हाईकोर्ट प्रशासन ने 15 जून से शुरू होने वाले सप्ताह की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। नियमित कामकाज शुरू होने के साथ ही लंबित मामलों की सुनवाई फिर से सामान्य तरीके से की जाएगी।

बिना फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा राशन, खाद्य विभाग ने नियमों में किया बदलाव

रायपुर, 14 जून 2026। अगर आप रायपुर में राशन कार्ड होल्डर हैं, तो अब सरकारी दुकान पर जाकर फिंगरप्रिंट लगाना ही पड़ेगा। खाद्य विभाग ने राशन वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ओटीपी के जरिए राशन लेने की सुविधा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अचानक दुकानों पर पहुंची संचालक : खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी ने रायपुर की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देवेन्द्रनगर स्थित राशन दुकान का जायजा लिया। इस व्यवस्था को खुद परखने के लिए उन्होंने अपने राशन कार्ड से बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगर लगाकर 20 किलो एपीएल चावल खरीदा और बाकायदा दुकानदार को पैसे भी दिए।

इन लोगों को मिलेगी छूट, लेकिन है एक शर्त : नया नियम सख्ती से लागू है, लेकिन कुछ मजबूरियों को विभाग ने समझा है। अगर परिवार में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं या 10 साल से छोटे बच्चे हैं और उनका फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं हो रहा, तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। ऐसे विशेष मामलों में ही ओटीपी के जरिए राशन दिया जाएगा। फिंगर प्रिंट बनाकर विभाग को देनी होगी। फिंगर मैच न होने पर दुकानदार को पहले परिया के खाद्य निरीक्षक से बात करनी होगी, उसके बाद ही ओटीपी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दुकानदारों को सीधी चेतावनी : जिला खाद्य नियंत्रक ने सभी दुकान



संचालकों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि अपनी मर्जी से किसी को भी ओटीपी के जरिए राशन नहीं देना है। अगर किसी दुकानदार ने बिना अनुमति के ओटीपी सिस्टम का इस्तेमाल किया, तो उन पर गज गिर सकती है। अधिकारियों ने मोवा और देवेन्द्रनगर की दुकानों में हितग्राहियों से बातचीत की। वहां लोगों ने बताया कि फिंगरप्रिंट से राशन लेने में अब कोई परेशानी नहीं आ रही है। सिस्टम में अच पहले से ज्यादा स्मूद हो गया है। विभाग का साफ कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक जरूरी है। राशन लेने जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार लिंक है, ताकि दुकान पर पहुंचकर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

राम मंदिर चोरी केस... विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष का बड़ा बयान आलोक कुमार बोले- रामजी के एक-एक पैसे के लिए ट्रस्ट जवाबदेह, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा मिलेगी

रायपुर, 14 जून 2026। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने रायपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद घटना सामने आई है तो संदेह का पूरी तरह निवारण होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट भगवान राम के एक-एक पैसे के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यही वजह है कि मामले की निष्पक्ष और खुली जांच की मांग खुद तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की है। ट्रस्ट के आग्रह पर बनी विशेष जांच दल : विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री से विशेष जांच दल गठित करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद तीन सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जांच दल में शामिल अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच का व्यापक अनुभव है और ट्रस्ट जांच में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि, हम सभी इस घटना से आहत हैं। लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए हमने शुरूआत से ही कहा है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी सांसदों द्वारा सवाल उठाने तथा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर भी आलोक कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि, कुछ राजनीतिक दल इस मामले में दखल खड़ा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा फेरबदल : 18 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले, रायपुर जोन कमिश्नर भी बदले गए

रायपुर, 14 जून 2026। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में पदस्थ 18 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम के जोन आयुक्त अरुण कुमार धुव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाकर दत्तेवाड़ा भेजा गया है। वहीं, दत्तेवाड़ा में पदस्थ वी.के.एस. पलदास को नगर पंचायत भोपालपट्टम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तत्काल सूची में कवर्धा, धमधा, दीपका, गौरला, चांपा, आरंग, कोंडागांव और दत्तेवाड़ा समेत कई नगरीय निकाय शामिल हैं। रोहित कुमार साहू को कवर्धा से धमधा, राजेश



गुप्ता को दीपका से गौरला और सचिन गुप्ता को बेरला से कोंडागांव स्थानांतरित किया गया है। शीतल चंद्रवंशी को आरंग से चांपा भेजा गया है। आदेश में जामुल, धर्मजयगढ़, बड़ी करेली, बेरला, केशकाल और बलौदाबाजार में पदस्थ अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। कुछ अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा गया है, जबकि कुछ को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नई जिम्मेदारी दी गई है।

7 दिन में जॉइन नहीं किया तो ठेकेगा वेतन

नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि, सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर 7 दिनों के भीतर नई जगह कार्यभार ग्रहण करना होगा। तय समय में जॉइनिंग नहीं करने पर पुराने स्थान से वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। यदि वेतन निकाला जाता है तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह तबादला आदेश जारी किया गया है। आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव द्वारा जारी किया गया।

शिक्षक भर्ती का बड़ा अवसर : एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती

जगदलपुर, 14 जून 2026। जगदलपुर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भर्ती के लिए 30 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक प्रयास आवासीय विद्यालय, धुरगुड़ा (जगदलपुर) में ऑफ-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जरूरी योग्यता वाले ही आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 21 जून 2026

तक गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निर्धारित लिंक पर जाकर फॉर्म भरना होगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेज, दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा अन्य जरूरी प्रमाण-पत्र साथ लाने होंगे। भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी आवेदन लिंक पर उपलब्ध है। इधर, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र

यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएगी और इसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री के अनुसार, व्यापक भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों में जुटा हुआ है और तय कार्यक्रम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उच्चकृत विद्यालयों में करीब 5 हजार शिक्षकों की आवश्यकता है। पूर्व में भर्ती प्रक्रिया विभिन्न कारणों से पूरी नहीं